● वर्ष-6
● अंक-84
रायपुर, मंगलवार
03 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

|| संगछध्वम् संवदध्वम् ||

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8›› नितिन नवीन का कांग्रेस...

युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित, युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान

2047 के विकसित भारत की बागडोर युवाओं के हाथों में : मनसुख मांडविया

रायपुर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में आज की युवा पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब एक मजबूत और विकसित भारत की बागडोर इसी अमृत पीढ़ी के हाथों में होगी। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और देश के सर्वांगीण विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया सोमवार को जगदलपुर के कुम्हरावण्ड स्थित शासकीय कृषि महाविद्यालय के सभागार में आयोजित श्युवा संवादश् कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने युवाओं से सीधे संवाद कर लोकतंत्र, रोजगार, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनकी प्राथमिक भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया माय भारत (डल ठींतंज) डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के युवाओं को नवाचार, मार्गदर्शन, स्वयंसेवा और करियर के नए अवसर उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इसके माध्यम से पूरे देश में एक लाख युवा नेतृत्वकर्ता तैयार



करने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है, जो आगे चलकर नीति-निर्माण और जनसेवा में अपनी प्रभावी भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने युवाओं से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण- विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की हर मानसिकता से मुक्ति, अपनी महान विरासत पर गर्व, एकता एवं एकजुटता तथा अपने नागरिक कर्तव्यों का निष्ठा से पालन को अपने जीवन में पूरी तरह अपनाने का संकल्प लेने को कहा। उन्होंने बल दिया कि युवा चाहे शिक्षा, प्रशासन, उद्यमिता या किसी भी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, उनके लिए हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर के युवा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने उपस्थित युवाओं को राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप और जगदलपुर विधायक किरण देव सिंह ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे।

लोकतंत्र की मजबूती और बस्तर के पर्यटन पर चर्चा

संवाद सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छात्र प्रांजल से विशेष रूप से मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर चर्चा की। उन्होंने लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए पारदर्शी, त्रुटिरहित मतदाता सूची और निष्पक्ष मतदान के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि युवाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से देश के शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के युवा संवाद कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। इस अवसर पर बस्तर की प्रशंसा करते हुए डॉ. मांडविया ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात का विशेष उल्लेख किया तथा क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं की सराहना की।

अराजकता से सत्ता हासिल करना चाहती है कांग्रेस : अमित शाह

'कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है'

हैदराबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह लगातार चुनावी हार का सामना करने के बाद अराजकता के जरिये सत्ता हासिल करने और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यहां अपनी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा से पहले एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही। उन्होंने कहा, नागरिकों ने इन हमलों से अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कमर कस ली है। अमित शाह सोमवार शाम इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यह पदयात्रा बशीरबाग स्थित बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा से शुरू हुई। यहां मोअज्जम जही मार्केट तक जाएगी। शाह सोमवार दोपहर को यहां बेगमपेट हवाई अड्डे पहुंचे। वह पदयात्रा में शामिल होने के लिए यहां आए हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना भाजपा के अन्य नेताओं ने हवाई अड्डे पर शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया।



पदयात्रा में जनता को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, आज मैं हैदराबाद की इस पवित्र भूमि पर लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले मां भाग्य लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करता हूं और सरदार पटेल साहब को भी मनपूर्वक नमन कर अपनी बात की शुरुआत करता हूं।

उन्होंने कहा, अगर सरदार उस वक्त निजाम को न झुकाते तो हैदराबाद आज भारत का हिस्सा न होता। वो सरदार साहब ही थे, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को झुकाकर हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया। तेलंगाना को भारत का हिस्सा बनाया। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी कोमराम भीम और रामजी गौड को भी मनपूर्वक प्रणाम करता हूं।

इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर शाह ने कहा, आज हैदराबाद में हजारों-हजारों की संख्या सड़क पर खड़ी है। कल दिल्ली में भी एक रैली हुई थी। राहुल जी की रैली हुई थी। इन्होंने कहा वोट बचाओ रैली है। ये वोट बचाओ रैली नहीं थी, घुसपैठिया बचाओ रैली थी। कांग्रेस पार्टी एसआईआर को रोककर देश की मतदाता सूची से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहती है। मगर मैं आज कहने आया हूं राहुल जी, रेवंत रेड्डी जी जितना जोर लगाना है लगा लो..भारतीय जनता पार्टी एक-एक घुसपैठिए को मतदाता सूची और देश से बाहर निकालकर ही दम लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इन टिप्पणियों में रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया ब्लॉक की रैली का जवाब दिए जाने की उम्मीद थी। इस रैली में गठबंधन ने भाजपा की आलोचना की थी।

भारत की ताकत बनी रिन्यूएबल एनर्जी : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत है। देश अगले 10-11 वर्षों में लगभग 500 जीडब्ल्यू की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह एक सुखद संयोग है कि इस शिखर सम्मेलन के साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नौवीं सभा भी आयोजित हो रही है। ग्रीन हाइड्रोजन पर चौथे सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि भी यहां मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इस



साल के आयोजन का दायरा काफी व्यापक है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व संकटों का सामना किया है। कोविड-19 महामारी से लेकर पश्चिम एशिया के संकट तक, दुनिया को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पश्चिम एशिया का संकट अभी भी जारी है। हालांकि, 140 करोड़ भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हमने अब तक इस संकट को बहुत प्रभावी ढंग से संभाला है।

पीएम मोदी ने आगे कहा, अगर भारत ने पिछले एक दशक में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश नहीं किया होता। इसके लिए नई प्रणालियां विकसित नहीं की होतीं, तो हमारा संकट दुनिया के बाकी हिस्सों के सामने आए संकट से कहीं अधिक गंभीर हो सकता था। इस वैश्विक संकट ने हर देश को एक स्पष्ट संदेश दिया है। ऊर्जा सुरक्षा सीधे तौर पर आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य स्वच्छ ऊर्जा में निहित है। अगर हम जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर बने रहते हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बार-बार रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा,हमारी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर आधारित है। भारत 500 जीडब्ल्यू के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में मजबूती से काम कर रहा है। हम पहले ही लगभग 300 जीडब्ल्यू का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। सौर और नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत अब दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है।



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो-2026 के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रदर्शनी स्टॉल पर राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा नीति, निवेश संभावनाओं और हरित ऊर्जा विकास पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

आखरी सांस तक सत्ता परिवर्तन नहीं होने देंगे : फडणवीस

मुंबई । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का सत्ता परिवर्तन अभियान लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान और संस्थाओं को कमजोर करने की गहरी साजिश है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में हुए राजनीतिक घटनाक्रम और संवैधानिक बदलाव एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हैं और भारत में भी इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मुंबई में भाजपा की ओर से आयोजित लोकतंत्र और संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि विपक्ष पहले लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन्हें बदलने का रास्ता तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव के जरिए एक सरकार की जगह दूसरी सरकार लाना सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का मतलब देश की राजनीतिक व्यवस्था, संविधान और संस्थाओं को बदलना है। फडणवीस ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का अधिकार हर किसी को है।



राहुल गांधी ने पीएम मोदी को दी खुली बहस की चुनौती

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी पर विदेशी मदद के सहारे सत्ता में बने रहने का आरोप लगाकर राजनीतिक विवाद तेज कर दिया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने और अब भी इसी मदद के सहारे इस पद पर बने हुए हैं। उन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था और विदेशी सोशल मीडिया को लेकर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि वह किसी भी मंच पर और किसी भी समय उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री इसलिए बहस के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि राहुल उनके बारे में क्या जानते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा, मोदी जी, इस देश से झूठ बोलना बंद कीजिए। आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने और विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं।



लोकतंत्र नहीं, हमें बचाओ कहिए : कपिल सिब्बल

नई दिल्ली। कांग्रेस और विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई वोट बचाओ, देश बचाओ रैली को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि इस रैली में करीब पांच से छह लाख लोग शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का शांतिपूर्ण तरीके से जुटना दिखाता है कि देश के नागरिक सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि अब उसे अपनी रैलियों का नाम लोकतंत्र बचाओ या देश बचाओ रखने के बजाय हमें बचाओ रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विपक्ष की रैली में जुटी भीड़ से चिंतित है। कपिल सिब्बल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रामलीला मैदान में हुई रैली में उनके अनुमान के मुताबिक पांच से छह लाख लोग मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि कनॉट प्लेस और उससे जुड़ने वाली आसपास की सड़कों पर पूरी तरह जाम लगा हुआ था और कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं दे रही थी।



अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त चेतावनी

मुंबई। सोमवार 2 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेहद कड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अभिनेता इमरान खान ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा उन्हें जारी किए गए लीव इंडिया नोटिस (भारत छोड़ने के नोटिस) को अदालत में चुनौती दी थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक होने का अर्थ यह कतई नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक को भारत में राजनीतिक या सामाजिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने का अधिकार मिल जाता है। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा-यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश में ऐसी गतिविधि की होती, तो उसे अब तक वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता।इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान, इमरान खान के पक्ष ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कभी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया था।



पाँच राज्यों में बड़ा उलटफेरः वोटर्स की नाराजगी से ट्रंप को झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन से बढ़ती असंतुष्टि और अर्थव्यवस्था को संभालने के उनके तरीके से हो रही निराशा मंगलवार को मध्यावधि चुनावों के लिए मतदान केंद्रों पर जाने वाले अमेरिकियों के लिए डेमोक्रेट्स के पक्ष में काम कर सकती है। 3 नवंबर से पहले, द न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि रिपब्लिकन सीनेटरों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे छह महत्वपूर्ण राज्यों में से पांच में डेमोक्रेटिक सीनेट उम्मीदवार रिपब्लिकन से आगे चल रहे हैं। आयोवा में मुकाबला लगभग बराबरी का था, जबकि मिशिगन में डेमोक्रेट्स को दो अंकों की बढ़त हासिल थी, जो सर्वेक्षण में शामिल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वे सीनेट सीट का बचाव कर रहे हैं। चुनाव के दिन से पहले टाइम्स/सिएना के अंतिम सर्वे के नतीजे बताते हैं कि डेमोक्रेट्स के पास एक ऐतिहासिक मौका हो सकता है। सीनेट में बहुमत हासिल करने के लिए, पार्टी को अपनी मौजूदा सीटें बचाए रखने के साथ-साथ रिपब्लिकन के कब्जे वाली कम से कम चार सीटें अपने पाले में करनी होंगी।



सौरभ चंद्राकर एक्शन तेज, भगोड़ा घोषित करने ईडी ने लगाई अर्जी

नयी दिल्ली/रायपुर। दो नवंबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने और उसकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, ईडी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चंद्राकर का वानुअतु का पासपोर्ट रद्द करने की मांग भी की है।

आरोप है कि उसने यह पासपोर्ट मई 2022 में भारत छोड़ने के तुरंत बाद हासिल किया था। चंद्राकर को रविवार को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। अधिकारियों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि ईडी ने नवंबर 2024 में रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें चंद्रकार और महादेव सट्टेबाजी ऐप के सह-प्रवर्तक रवि उप्पल को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' (एफईओए) के तहत 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने का अनुरोध किया गया था।

उन्होंने बताया कि चूंकि, इस मामले में सुनवाई कई बार टल चुकी है, इसलिए जांच एजेंसी ने अक्टूबर में उसी विशेष पीएमएलए अदालत में एक नयी अर्जी दाखिल की, जिसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ जारी मुकदमे में तत्काल सुनवाई और जल्द निपटारा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, विशेष अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए पांच दिसंबर की तारीख तय की है। उन्होंने कहा कि चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत वापस लाए जाने के बावजूद उसके खिलाफ ईडी की एफईओए याचिका वैध है; क्योंकि उसने खुद कानून के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है, बल्कि एजेंसियों के प्रयासों से उसे जांच का सामना करने के लिए लाया गया है।



अधिकारियों ने बताया कि एक बार जब किसी व्यक्ति को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित कर दिया जाता है, तो ईडी को उसकी मुख्य और संबंधित संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल जाता है। उन्होंने बताया कि ईडी ने चंद्राकर के खिलाफ दर्ज मामले में कुल 1,700 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य) की संपत्तियां कुर्क की हैं। यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने भारत और विदेश में चंद्राकर की कई संपत्तियों का पता लगाया है, जिन्हें एफईओए के तहत जब्त किया जाएगा।

इनमें से कई संपत्तियां बेनामी बताई जा रही हैं। केंद्र सरकार 2018 में एफईओए लेकर आई थी, ताकि कम से कम 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के बाद कानून से बचने के लिए भारत से भाग जाने वाले लोगों को न्याय के दायरे में लाया जा सके। इससे पहले, कारोबारी विजय माल्या और नीरव मोदी को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया जा चुका है।

अधिकारियों के अनुसार, ईडी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर चंद्रकार का वानुअतु का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि चंद्रकार ने यह पासपोर्ट 16 फरवरी 2022 को भारत से दुबई जाने के कुछ समय बाद मई 2022 में हासिल किया था। अधिकारियों ने कहा कि भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है और ईडी ने पाया है कि चंद्राकर जन्म से भारतीय नागरिक है तथा उसने भारतीय पासपोर्ट रखते हुए ही वानुअतु का पासपोर्ट हासिल किया था।

ईडी ने चंद्राकर को महादेव सट्टेबाजी ऐप का मुख्य प्रवर्तक, रकम इकट्ठा करने वाला और लाभार्थी बताया है तथा अक्टूबर 2023 में दाखिल आरोपपत्र में उसे आरोपी नंबर-1 के तौर पर नामजद किया है। ईडी का दावा है कि महादेव ऐप के संचालकों की छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं और नौकरशाहों के साथ सांठगांठ थी। अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर 2020 तक चंद्रकार छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर में अपने परिवार की कंपनी की ओर से संचालित जूस की दुकान में काम करता था, लेकिन अगले दो वर्षों में उसने दुबई से हजारों कर्मचारियों के साथ सट्टेबाजी का कारोबार शुरू कर दिया। ईडी महादेव ऐप के सह-प्रवर्तक रवि उप्पल के प्रत्यर्पण के लिए भी अनुरोध भेज रही है, जिसके दुबई में होने का अंदेशा है।

अराजकता के खिलाफ जगदलपुर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री मांडविया हुए शामिल



बस्तर। बस्तर में बीजेपी ने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली। जगदलपुर शहर में शुरू हुई इस रैली और पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। उनके अलावा इस पदयात्रा में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में आयोजित सभा को संबोधित करने के बाद शहर में रैली निकाली गई। इस रैली में बस्तर जिले के विभिन्न मंडल से कार्यकर्ता और जनता बड़ी संख्या में पहुंचे।

मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतदेश में कांग्रेस और उनके साथी पक्षों को देश की जनता ने नकार दिया है। अपना अस्तित्व बचाने के किये देश में कांग्रेस के नेता अराजकता फैला रहे हैं और षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ पूरे देश में आम जनता सड़क पर उतर चुकी है।

मनसुख मांडविया ने आगे कहा कि देश में सभी जाति वर्ग और व्यापारी समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता पीएम मोदी के समर्धन में बाहर आए हुए हैं। आज जगदलपुर में व्यापारी वर्ग, कारोबारी वर्ग और संस्था के लोग अराजकता के खिलाफ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। सभी लोग संविधान बचाने के लिए एक साथ आए हैं। इससे पहले रविवार को इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली निकाली। राहुल गांधी ने इस महारैली की अगुवाई की और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार नहीं होते तो न नरेंद्र मोदी पीएम बनते और न ही अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बनते।

12 नवंबर से ड्राइवर संघ का स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन

- **आंदोलन के चलते जरूरी सामान समेत कई व्यवस्था हो सकती है प्रभावित मांगें पूरी नहीं होने पर बस्तर की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक..!**



बस्तर। अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद अब ड्राइवर संघ हड़ताल करने जा रहा है। 12 नवंबर से छत्तीसगढ़ में सभी ड्राइवर स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन पर जा रहे हैं। आंदोलन की तैयारी बस्तर में जोरों से चल रही है। रविवार को आयोजित बैठक में ड्राइवर संघ ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है।

इससे बस्तर में भी परेशानी बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। संयुक्त ड्राइवर संघ के हड़ताल से राशन वितरण प्रणाली, सब्जी मार्केट, पेट्रोल डीजल परिवहन, खनिज संपदा परिवहन, यात्री बसों का संचालन, शासकीय वाहन से कार्यालय पहुंचने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे।

लोकल ड्राइवर संघ के संभागीय अध्यक्ष दुर्जनराम नाग ने बताया कि बीते दिनों ड्राइवर संघ ने ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर, ड्राइवर एक दिवस जैसी मांगों को लेकर हड़ताल की थी। इस पर शासन-प्रशासन की ओर से मांगें पूरी होने का आश्वासन मिला जिसके बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई। लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिसके चलते राजधानी रायपुर में जॉइंट कमेटी के तहत 33 जिलों के सभी ड्राइवर संघ के पदाधिकारियों ने बैठक की। यह निर्णय लिया गया है कि यदि समय पर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी 12 नंवबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे।

ड्राइवर संघ का कहना है कि सड़कों में एक्सीडेंट होने पर बिना सत्य जाने ड्राइवर को दोषी ठहराकर मारपीट की जाती है। रास्तों में गुंडों के मारपीट करने का भी मामला सामने आता है। ऐसे मामले शासन प्रशासन के संज्ञान में हैं। इन मामलों को लेकर जंतर मंतर में भी भारत के 28 राज्यों के चालकों ने आंदोलन किया था। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसीलिए एकजुट होकर अपने हक अधिकार को लेना चाह रहे हैं।

जिला महासचिव नलसिंग नाग का कहना है कि अपनी मांगों को और 12 नवंबर के आंदोलन को लेकर जिला कलेक्टर, एसपी बस्तर, परिवहन विभाग, लोकल परिवहन संघ, ट्रांसपोर्टर, सहित सभी लोगो को पत्राचार किया गया है। नलसिंग का कहना है कि लगभग सभी ड्राइवर गरीब हैं। किसी कारणवश उनकी मौत होने पर ना प्रशासन सहयोग करता है और ना ही गाड़ी मालिक सहयोग करते हैं।

आम नागरिक को परेशानी होने पर वे आंदोलन करते हैं और उन्हें प्रशासन सहयोग करता है। ड्राइवर संघ की भी मांग है कि घटना दुर्घटनाओं में उन्हें भी घायल अथवा मृत्यु होने पर उचित मुआवजा राशि प्रदान किया जाए।

बीजापुर में बस पलटने के मामले पर संभागीय अध्यक्ष का कहना है कि ड्राइवर रात-दिन गाड़ियां चलाते हैं। कई बार 24 घंटा भी गाड़ी चलाना पड़ता है। गाड़ी मालिक उनसे काम लेते हैं। ड्राइवर की कोई समय सीमा तय नहीं है। जिसके कारण ड्राइवर रात में थका महसूस करता है। और घटनाएं भी होती है। इसीलिए शासन प्रशासन केवल 8 घंटा ही ड्यूटी करवाए।

बलरामपुर के बंगाली मूर्तिकारों का दर्द

बढ़ती महंगाई और कम बिक्री ने बढ़ाई चिंता



बलरामपुर रामानुजगंज। रामानुजगंज में दीपावली त्यौहार से पहले बंगाली मूर्तिकार परंपरागत रूप से मां लक्ष्मी, काली, सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। रामानुजगंज के केरवाशीला गांव में बंगाली मूर्तिकार हर साल मूर्तियां तैयार करते हैं। मूर्तिकारों की आजीविका इन्हीं से जुड़ी है।दीपावली में होने वाली आमदनी इन मूर्तिकारों के लिए अगले तीन से चार महीनों का आर्थिक सहारा बनता है। केरवाशीला गांव की रहने वाली महिला मूर्तिकार रंजीता सरकार ने बताया कि दीपावली पूजा के लिए वो देवी लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार कर रही हैं। प्रतिमा के साथ सबकी सवारी उल्लू, मूसक और हंस भी हैं। इस बारे में केरवाशीला गांव के ही निवासी प्रताप सरकार ने कहा कि अभी दीपावली के लिए हमारे यहां मां लक्ष्मी, काली का मूर्ति बना रहे हैं इस बार पांच छह मूर्तियों के ही ऑर्डर मिले हैं। इनकी कीमत दो हजार रूपए से तीन हजार रूपए तक रखा गया है।

युवा मूर्तिकार प्रताप सरकार का कहना है कि इस मूर्ति कला व्यवसाय में मेहनत के मुताबिक उन्हें फायदा नहीं मिल पाता है। इसके बावजूद अपने इस पैतृक व्यवसाय को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने के लिए हम इस काम को कर रहे हैं।

ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले अंतरजिला 9 आरोपी गिरफ्तार



बेमेतरा। सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों से डीजल चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का बेमेतरा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दो स्कार्पियो सहित 36 लाख रुपये से ज्यादा की सामग्री जब्त की गई है। यह गिरोह बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर-चांपा जिले में सक्रिय था। पुलिस की इस कार्रवाई से चार जिलों में चल रहे डीजल चोरी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। मामले की शुरुआत नांदघाट थाना क्षेत्र के रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय मार्ग पर ग्राम टेमरी स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई चोरी की घटना से हुई। यहां खड़े दो कंटेनर ट्रकों को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया था। आरोपियों ने ट्रकों की डीजल टंकियों के लॉक तोड़कर करीब 550 लीटर डीजल चोरी किया। घटना के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर नांदघाट पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (डुक्कर) के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में नांदघाट थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल से मिले सुरागों, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की। लगातार जांच और पतासाजी के बाद पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तीन जगहों पर डीजल चोरी की घटनाएं सामने आई थी, लगातार प्रयास के बाद 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें 2 वाहन मालिक भी है। चोरी किया हुआ लगभग 500 लीटर डीजल और 1 लाख 54 हजार रुपये जब्त हुआ। ये अपने साथ जरकिन और टुल्लु पंप यूज करते थे, 10 से 15 मिनट में ये चोरी की घटना को अंजाम देते थे ङ्क त्रिलोक बंसल, पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा निखिलदास उम्र 23 वर्ष, ग्राम खिसारा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा, सुरज कुर्रे उम्र 19 साल निवासी ग्राम खिसोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा, मनीष कुमार जांगड़े उर्फ मोना उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम भिलाई थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा, संजीत कुमार अनंत उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम बुचीहरदी थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा, जयकरण खुंटे उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम खिसोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा, शुभम जांगड़े उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम भिलाई थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा, उपेन्द्र उर्फ ननकी यादव उम्र 42 साल ग्राम खिसोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा, रेशम उर्फ मोनु यादव उम्र 26 साल बजरंग नगर बलौदा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा, राजेश कोयल उम्र 45 साल ग्राम खिसोरा थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा पूछताछ में गिरोह के अपराध करने का तरीका सामने आया। आरोपी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ियों में फर्जी डिजिटल नंबर प्लेट लगाकर अलग-अलग जिलों में घूमते थे। बताया गया कि आरोपी सीजी 10 बीए 7969 नंबर की फर्जी प्लेट का इस्तेमाल करते थे, ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। रात के समय सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों को निशाना बनाकर डीजल टंकियों के लॉक तोड़ते और बड़ी मात्रा में डीजल निकालकर चोरी कर लेते थे। बाद में चोरी के डीजल को बाजार में बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी केवल बेमेतरा जिले तक सीमित नहीं थे, बल्कि बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर-चांपा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी डीजल चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो स्कार्पियो सहित 36 लाख रुपये से अधिक का सामग्री जब्त किया है। पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई को बेमेतरा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

141 पटवारियों को सेवा उल्लंघन का नोटिस



जांजगीर चांपा। पीवी एप के विरोध में राजस्व पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के 18 दिन बाद जिला प्रशासन सख्त हो गई है। जिला प्रशासन ने हड़ताल करने वाले पटवारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने 141 पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस जारी किया है, साथ ही राजस्व पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव और ज्योतिष कुमार सर्वे को निलंबित कर दिया है। जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद राजस्व पटवारी संघ मे आक्रोश व्याप्त है और राज्य स्थापना दिवस के दिन सर्विस ब्रेक के नोटिस की प्रति जलाने का एलान कर दिया है। जिले में कुल 156 पटवारी पदस्थ है, जो 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल है। शासकीय काम में लगातार अनुपस्थित होने के कारण उन्हें वापस काम पर लौटने के लिए कहा गया, जिसमें से 15 पटवारी काम पर वापस लौट गए। वापस लौटे पटवारियों में 13 परिवीक्षाधीन पटवारी और 2 ऐसे पटवारी शामिल हैं, जो हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे। जांजगीर चांपा जिला के दो पटवारियों को शिवरीनारायण और जांजगीर एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। दोनों पटवारियों के निलंबन का कारण कर्तव्य में लापरवाही और अनधिकृत अनुपस्थिति को प्रमुख कारण बताया गया, साथ ही एक पटवारी पर पूर्व में अपराध पंजीबद्ध होने के कारण निलंबन की कार्रवाई करना बताया गया है। अनुविभागीय अधिकारी शिवरीनारायण ने धर्मेंद्र यादव, पटवारी हल्का नंबर 13, तहसील शिवरीनारायण के विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही एवं अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई की गई है। उनकी अनुपस्थिति से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फौती, अभिलेख दुरुस्ती, धान फसल का डिजिटल क्रॉप सर्वे, फसल गिरदावरी, धान खरीदी एवं अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

मरवाही वनमंडल में विचरण कर रहे हाथियों की संख्या बढ़ी

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही वनमंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में हाथियों के बड़े दल की लगातार मौजूदगी बनी हुई है। करीब 10 दिन पहले 53 हाथियों का दल कोरबा जिले के पसान परिक्षेत्र से मरवाही वनमंडल पहुंचा था। इसके बाद वन विभाग ने ड्रोन की मदद से हाथियों की गिनती कराई, जिसमें दल की संख्या बढ़कर 62 सामने आई है। जानकारी के अनुसार, मरवाही वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहा हाथियों का दल वर्तमान में दो अलग-अलग समूहों में बंट गया है। पहला समूह कक्ष क्रमांक 33 नाका परिसर में मौजूद है, जबकि दूसरा समूह जुनवानी डेम के पास विचरण कर रहा है। दोनों समूहों की अलग-अलग लोकेशन होने के कारण वन विभाग की ओर से उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से हाथियों की संख्या और उनकी मौजूदगी वाले स्थानों की जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचाव किया जा सके। वन विभाग ने गांवों के ग्रामीणों के लिए सतर्कता बरतने की अपील की है।

सरपंच संघ ने हाथों में कटोरा लेकर मांगी भीख

गरियाबंद। जिले की ग्राम पंचायतों में लंबित भुगतान और आर्थिक संकट को लेकर जिला सरपंच संघ के नेतृत्व में सरपंचों, उपसरपंचों और पंचों ने सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पंचायतों की आर्थिक बदहाली को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हुए कटोरा लेकर शासन-प्रशासन से लंबित राशि जारी करने की मांग की गई। रैली कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू होकर सिविल लाइन होते हुए बस स्टैंड पहुंची। यहां से प्रदर्शनकारी तिरंगा चौक पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। बड़ी संख्या में पहुंचे सरपंच, उपसरपंच और पंच हाथों में कटोरा लेकर तिरंगा चौक पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य कराने के बावजूद भुगतान नहीं मिलने से जनप्रतिनिधियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जिला सरपंच संघ द्वारा शासन-प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत लगभग 30 करोड़ रुपये के कार्य कराए जा चुके हैं।

कवर्धा में सियार ने बाइक से जा रहे ग्रामीण पर हमला

कबीरधाम। जिले में वन्य प्राणियों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। देर शाम एक ग्रामीण पर सियार ने हमला कर दिया, जिससे उसके हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। इससे पहले पिछले दिनों लोहारा वन परिक्षेत्र में तेंदुए के हमले से एक ग्रामीण घायल हो गया था।कबीरधाम जिले के छपरी गांव में देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बाइक से गुजर रहे एक ग्रामीण पर सियार ने अचानक हमला कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सियार को पकड़कर जाली में बंद कर दिया। इस घटना ने गांव में वन्य प्राणियों की मौजूदगी और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दूसरी घटना लोहारा वन परिक्षेत्र के कुटकीपारा गांव के पास जंगल की है। यहां लकड़ी काटने गए ग्रामीण तेक राम ध्रुव पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। हमले में उसके हाथ और कंधे पर चोटें आईं। घायल को तत्काल लोहारा उपस्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल ग्रामीण की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

अर्नब तूफान का आंकलन करने प्रशासन पहुंचे खेत

जांजगीर चांपा। अर्नब चक्रवात से आई बारिश और तूफान से फसल को हुए नुकसान और प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कलेक्टर ने कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ नवागढ़, पामगढ़ और अकलतरा तहसील क्षेत्र में खेतों का निरीक्षण किया और किसानों को शासन के नियमानुसार आरबीसी 6-4 के तहत सहायता मिलने की जानकारी दी। चक्रवात अर्नब के प्रभाव से हुई वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान एवं प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। समीक्षा के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अधिकारियों की बैठक ली और सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदारों, कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ निरीक्षण कर फसल क्षति का वास्तविक आकलन करने के लिए निर्देश दिए गये।

देश का पहला सौर गांव बना राजनांदगांव जिले का खैरा

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के 889 की आबादी वाले गांव खैरा में अब हर घर अपनी बिजली खुद बना रहा है। गांव के सभी 141 घरों की छत पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लग चुका है। इसके साथ ही खैरा पीएम सूर्य घर योजना के तहत शत-प्रतिशत रूफटॉप सोलर लक्ष्य पूरा करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। हर घर में 2 किलोवाट का सिस्टम लगा है, जिससे गांव की कुल स्थापित क्षमता लगभग 282 किलोवाट हो गई है । ग्रामीणों को कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ा। केंद्र और राज्य की सब्सिडी के बाद की शेष लागत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के सहयोग से पूरी की गई। ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचने में यह योजना अक्सर कठिनाई का सामना करती रही है। ऐसे में खैरा की खासियत केवल पैनलों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वे किन घरों तक पहुंचे। 141 सोलर-युक्त घरों में से 93 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों के हैं।

पहली बार झिरका पहुंचे डेनमार्क के विदेशी मेहमान

- **नक्सलवाद के साये से निकलकर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर दंतेवाड़ा**



दंतेवाड़ा। बदलते बस्तर की तस्वीर अब देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाने लगी है। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के बाद क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच अब विदेशी पर्यटक भी दक्षिण बस्तर के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण दंतेवाड़ा जिले के झिरका ग्राम में देखने को मिला, जहां पहली बार डेनमार्क से चार विदेशी पर्यटक पहुंचे। जिले में ग्रामीण एवं जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। झिरका ग्राम स्थित प्रसिद्ध झारालावा जलप्रपात के क्षेत्र में पहुंचे विदेशी पर्यटकों का स्थानीय पर्यटन समिति और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक एवं आत्मीयता के साथ स्वागत किया। डेनमार्क से आए पर्यटकों ने झिरका की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक खानपान और ग्रामीण जीवनशैली को करीब से जानने का अवसर प्राप्त किया। उनके लिए यह भ्रमण केवल प्राकृतिक स्थलों को देखने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बस्तर की परंपराओं और स्थानीय जीवन को समझने का भी अनूठा अनुभव बना।भ्रमण के दौरान पर्यटकों ने बस्तर की प्रसिद्ध पारंपरिक चापड़ा चटनी बनाने की पूरी प्रक्रिया देखी। ग्रामीणों ने उन्हें इस पारंपरिक व्यंजन को तैयार करने की विधि और उससे जुड़ी स्थानीय परंपराओं की जानकारी दी। पर्यटकों ने चापड़ा चटनी के अनूठे स्वाद का भी आनंद लिया। इसके बाद विदेशी मेहमानों ने गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों के रहन-सहन, खानपान और पारंपरिक गतिविधियों को करीब से देखा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर महुआ से जुड़े पारंपरिक निर्माण की प्रक्रिया को भी समझा और बस्तर की जनजातीय संस्कृति में महुआ के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी प्राप्त की। झिरका ग्राम में पहली बार चार विदेशी पर्यटकों का पहुंचना ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। झारालावा जलप्रपात की प्राकृतिक छटा, हरियाली, स्थानीय व्यंजन और जनजातीय परंपराएं इस क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से विशिष्ट बनाती हैं। इस तरह की पहल से दंतेवाड़ा के उन प्राकृतिक स्थलों को भी पहचान मिलने की संभावना है, जो अब तक मुख्यधारा के पर्यटन मानचित्र पर अधिक चर्चित नहीं रहे हैं। साथ ही ग्रामीण पर्यटन के विस्तार से स्थानीय युवाओं, महिला स्व-सहायता समूहों और पर्यटन समितियों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं।

कबीरधाम में 145 केंद्रों पर होगी खरीदी



कवर्धा। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। इसे लेकर कबीरधाम जिले में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस वर्ष जिले में 37 नए धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं, जिसके बाद खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। वहीं किसानों की सुविधा के लिए 48 नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। खाद्य विभाग का दावा है कि 10 नवंबर तक सभी खरीदी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन ने बताया कि जिले में इस बार एक लाख 10 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की जाएगी। किसानों को टोकन के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत दो एकड़ तक भूमि वाले किसानों को एक टोकन मिलेगा, जबकि पांच से दस एकड़ तक भूमि वाले किसानों को दो टोकन दिए जाएंगे। किसान संबंधित मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। धान खरीदी के दौरान बारदानों की कमी न हो, इसके लिए भी विभाग ने तैयारी की है। इस बार पीडीएस और मिलर्स से मिलने वाले पुराने बारदानों के साथ मार्कफेड द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नए बारदानों का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी ओर, दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खपाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था मजबूत की है। जिले के छह सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। यहां तहसीलदार, खाद्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें वाहनों की जांच करेंगी। अवैध भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए दिन-रात गश्त भी की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

महादेव सट्टा ऐप मामले में दिल्ली कोर्ट में पेश हुए सौरभ चंद्राकर

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में



आरोपी सौरभ चंद्राकर को सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोर्ट से सौरभ चंद्राकर की ट्रांजिट रिमांड मांगी है। लंच यानि ढाई बजे के बाद मामले में सुनवाई होगी। इस दौरान सीबीआई ने उसका फर्जी पासपोर्ट भी जब्त किया। सुनवाई के दौरान सौरभ चंद्राकर के बचाव पक्ष के वकील ने उसकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सवाल उठाए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जब भारत सरकार ने ओमान को केवल मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई की जानकारी दी थी तो फिर सीबीआई ने किस आधार पर सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया? वहीं, सीबीआई ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब देते हुए कहा कि ओमान सरकार के जिस पुराने आदेश का हवाला दिया जा रहा है, वह पूर्व का आदेश है। सीबीआई के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी नए आदेश के तहत की गई है, जिसमें किसी विशेष जांच एजेंसी का उल्लेख नहीं है।

अर्नब के बाद मुरासु तूफान से फिर बदलेगा मौसम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान अर्नब के बाद अब एक और चक्रवात %मुरासु का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते प्रदेश में अगले तीन दिनों तक बारिश और गरज-चमक की सक्रियता बढने की संभावना है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में यलो अलर्ट घोषित किया है। तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जतायी गई है। वैसे पिछले दो दिनों से आसमान पर बादल छाये हुए हैं हालांकि बीच बीच में धूप भी निकल रही है। उधर राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात मुरासु अब ताकतवर तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार सुबह यह चेन्नई से 260 और नेल्लोर से 290 किलोमीटर दूर था। तूफान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसके 2 नवंबर की रात से 3 नवंबर की सुबह के बीच ओंगोल के पास आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा चक्रवाती तूफान है। इससे पहले चक्रवात अर्नब 28 अक्टूबर को आंध्र के तट से टकराया था। मुरासु का असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में दिखने का अनुमान है। ओडिशा में 2 और 3 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 5 नवंबर तक आंधी-बारिश का दौर रह सकता है।

ई-रिक्शा खरीदने के लिए निर्माण महिला श्रमिकों को मिलेगा एक लाख का अनुदान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई-रिक्शा खरीदने पर 1,50,000/- या ई-रिक्शा क्रयमूल्य की 60 प्रतिशत राशि जो भी अधिकतम हो उक्त राशि का अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधीन छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू की गई है। योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुदान की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। इस सहायता से महिला श्रमिकों को आजीविका का नया साधन उपलब्ध होने के साथ ही उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की उन महिला निर्माण श्रमिकों को मिलेगा, जो संबंधित निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के स्व-सहायता समूहों को भी शामिल किया गया है। ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलने वाली एक लाख रुपए की अनुदान राशि का उपयोग केवल ई-रिक्शा क्रय करने के लिए ही किया जा सकेगा।

शहर के रिहायशी इलाके में पटाखा निर्माण, दो गिरफ्तार

रायपुर। दुर्घटना की संभावित कारणों को जानते हुए भी शहर के रिहायशी इलाके में पटाखा निर्माण का मामला गोलबाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामने आया है। वैसे ही कई दुकानों को संचालन भी गोलबाजार,चूड़ी लाइन गणेशराम नगर में हो भी रहा है,भले ही कुछ ने नियमागत परमिशन ले रखा होगा लेकिन दुर्घटना घटित होने पर बड़ा हादसा हो सकता है। गणेश राम नगर में शिव शक्ति पटाखा दुकान के ऊपर बने आवासीय कमरे में दीपावली पर बिक्री के लिए पटाखे तैयार किए जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 5 कार्टन तैयार पटाखे, अधबने पटाखे और निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एल्युमिनियम पाउडर जब्त किया गया। टीम ने पटाखे बनाने वाले कमरे को सील कर दिया है। मामले में दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, 1 नवंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गणेश राम नगर स्थित शिव शक्ति पटाखा दुकान का संचालक दुकान के ऊपर बने कमरे में दूसरे लोगों से पटाखे तैयार करवा रहा है। सूचना के आधार पर एसडीएम कार्यालय, नगर निगम के जोनल कमिश्नर और पर्यावरण अधिकारी के कार्यालय की संयुक्त टीम ने मौके पर जांच की।

राज्यपाल ने आसमान में देखा भारतीय वायु सेना का अद्भुत शौर्य, साहस और कौशल

सारंग के पांच हेलीकॉप्टरों के रोमांचकारी करतबों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, सेंध लेक में आयोजित भव्य एयर-शो बना आकर्षण का केंद्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर नवा रायपुर का आसमान सोमवार को भारतीय वायु सेना के अदम्य शौर्य, साहस, अनुशासन और अद्भुत उड़ान कौशल का साक्षी बना। सेंध लेक में आयोजित भारतीय वायु सेना की विश्वप्रसिद्ध सारंग एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम के भव्य एयर-शो में राज्यपाल श्री रमेन डेका शामिल हुए। इस अवसर पर आकाशगंगा स्काईडाइविंग टीम, गरुड़ कमांडोज और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के जांबाजों ने अपने साहसिक करतबों, सटीक नियंत्रण और उत्कृष्ट समन्वय से उपस्थित जनसमूह को रोमांचित कर दिया। पांच हेलीकॉप्टरों की आकर्षक फॉर्मेशन, हैरतअंगेज हवाई करतबों, आसमान में तिरंगे की मनमोहक छटा और वंदे मातरम की गूंज ने पूरे वातावरण को देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से सराबोर कर दिया।

राज्यपाल रमेन डेका ने भारतीय वायु सेना के जांबाजों के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित सारंग टीम का यह आयोजन हम सभी के लिए गौरव और प्रसन्नता का विषय है। वायु वीरों ने जिस साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और सटीक समन्वय के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया है, वह प्रत्येक नागरिक, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। यह आयोजन केवल रोमांचकारी हवाई करतबों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारतीय वायु सेना की उत्कृष्ट क्षमता, कठिन प्रशिक्षण, समर्पण और राष्ट्रसेवा की भावना का जीवंत परिचय है। उन्होंने प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कामना की, कि हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर विकास, प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहे। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस की खुशियों के बीच भारतीय वायु सेना के जांबाजों का यह अद्भुत प्रदर्शन प्रदेशवासियों के उत्साह और गौरव को और अधिक बढ़ा रहा है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि सारंग का अर्थ मोर होता है। जिस प्रकार मोर हमारे देश की विशिष्ट पहचान और सुंदरता का प्रतीक है, उसी प्रकार सारंग टीम भारतीय वायु सेना की गरिमा, उत्कृष्ट कौशल और अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हवाई प्रदर्शन के दौरान हेलीकॉप्टरों की विभिन्न फॉर्मेशन और साहसिक करतब भले ही देखने में सहज और सुंदर दिखाई देते हों, लेकिन इनके पीछे विस्तृत योजना, निरंतर अभ्यास, गहरी एकाग्रता और असाधारण समन्वय होता है। प्रत्येक पायलट को अपनी भूमिका के साथ-



साथ अपने साथियों की गतिविधियों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक-दूसरे पर अटूट विश्वास और सटीक तालमेल ही ऐसी अद्भुत प्रस्तुतियों को संभव बनाता है। उन्होंने कहा कि सारंग टीम का प्रदर्शन हमें यह महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अनुशासन, समर्पण, सामूहिक प्रयास और आपसी विश्वास से कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रदर्शन युवाओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने और सामूहिक प्रयासों से सफलता हासिल करने की प्रेरणा देता है।

एयर-शो का रोमांचकारी शुभारंभ भारतीय वायु सेना की प्रसिद्ध आकाशगंगा स्काईडाइविंग टीम ने किया। खुले आसमान से छलांग लगाते हुए टीम के जांबाजों ने अपने पैराशूट को कुशलतापूर्वक नियंत्रित कर अदम्य साहस, संतुलन और सटीकता का परिचय दिया। निर्धारित दिशा और गति के अनुरूप पैराशूट को नियंत्रित करते हुए स्काईडाइवर्स ने सेंध लेक के सामने निर्धारित स्थान पर सटीक लैंडिंग की। उनके इस साहसिक प्रदर्शन को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे और सफल लैंडिंग के बाद पूरा परिसर तालियों की गडग़ड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रस्तुति ने भारतीय वायु सेना के जवानों की शारीरिक दक्षता, मानसिक एकाग्रता और दृढ़ता और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण की प्रभावशाली झलक प्रस्तुत की।

आकाशगंगा टीम के प्रदर्शन के बाद भारतीय वायु सेना के गरुड़ कमांडोज ने अपने अदम्य साहस और विशेष ऑपरेशन की दक्षता का परिचय दिया। कमांडोज ने एयर-शो से पहले आठ हजार फीट की ऊंचाई से पैराशूट लैंडिंग कर दर्शकों को रोमांचित किया। इसके पश्चात एमआई-17 हेलीकॉप्टर से स्लिदरिंग का प्रदर्शन किया गया। हवा में स्थिर हेलीकॉप्टर से रस्सियों के सहारे नीचे उतरते जवानों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्धारित स्थान तक पहुंचने की अपनी दक्षता प्रदर्शित की। सेंध लेक के सामने कमांडोज ने रेस्क्यू एवं कॉम्बैट ऑपरेशन का प्रभावशाली प्रदर्शन कर अपनी परिचालन क्षमता, त्वरित कार्रवाई और कठिन परिस्थितियों में मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के कौशल का परिचय दिया। इसके पश्चात जवानों ने मंच को सलामी दी। उनके अनुशासित और साहसिक प्रदर्शन पर दर्शकों ने तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया।

एयर-शो का सबसे प्रमुख आकर्षण भारतीय वायु सेना की विश्वप्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम की शानदार प्रस्तुति रही। ग्रुप कैप्टन अभिजीत कुमार के नेतृत्व में टीम के पांच हेलीकॉप्टरों ने नवा रायपुर के आसमान में एक के बाद एक आकर्षक फॉर्मेशन और रोमांचकारी हवाई करतब प्रस्तुत किए।

पायलटों ने अत्यंत सटीक नियंत्रण, संतुलन और बेहतरीन समन्वय के साथ हेलीकॉप्टरों को उड़ाकर अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया। आसमान में एक साथ उड़ते पांच हेलीकॉप्टरों की आकर्षक फॉर्मेशन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

महादेव सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर का भारत प्रत्यर्पण बड़ी सफलता: साय

- मुख्यमंत्री ने सीबीआई और सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाए जाने को केंद्रीय जांच एजेंसियों की बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के माध्यम से महादेव सट्टा ऐप के अवैध कारोबार, इससे जुड़े पूरे नेटवर्क और प्रोटेक्शन मनी प्राप्त करने वाले लोगों के संबंध में महत्वपूर्ण खुलासे हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि महादेव सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर लंबे समय से विदेश में था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) लगातार प्रयास कर रही थी कि उसे भारत लाया जाए, ताकि इस पूरे प्रकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां



सामने आ सकें। सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से उसका भारत प्रत्यर्पण संभव हुआ है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सौरभ चंद्राकर का भारत प्रत्यर्पण एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस सफलता के लिए सीबीआई और सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में यह जानकारी भी सामने आएगी कि महादेव सट्टा ऐप के अवैध कारोबार से किन-किन लोगों को प्रोटेक्शन मनी दी जाती थी और इस पूरे मामले में किन लोगों की क्या भूमिका रही है। इससे जांच को नई दिशा मिलेगी और प्रकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

शहरी स्वच्छता और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को मिलेगी मजबूती: मंत्री राजवाड़े

- शिवनंदनपुर में 65.07 लाख रुपये की लागत से बनने वाले एमआरएफ-एसएलआरएम सेंटर का भूमिपूजन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले की नगर पंचायत शिवनंदनपुर में 65.07 लाख रुपये की लागत से बनने वाले एमआरएफ-एसएलआरएम सेंटर के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस केंद्र के निर्माण से नगर में कचरे के पृथक्करण, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

यह पहल नगर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के साथ स्वच्छ एवं सुंदर शिवनंदनपुर के निर्माण



की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र के माध्यम से कचरे के व्यवस्थित प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा और नगर को स्वच्छ बनाए रखने के प्रयासों को गति मिलेगी।

इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्री रितेश जायसवाल, श्री बाबूलाल अग्रवाल, श्री अजय गोयल, श्री ललित गोयल, श्री मनीबग्गा, श्री अंशुल गोयल सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

राजवाड़े के प्रयासों से ओड़गी में सड़क-पुल निर्माण को मिली स्वीकृति

सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड के ग्राम पंचायत खालबहारा में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से खालबहारा मेन रोड से पंचायत भवन तक 1.50 किलोमीटर लंबे मार्ग का पुल-पुलियों सहित निर्माण स्वीकृत हुआ है। लोक निर्माण विभाग ने इस कार्य के लिए 1 करोड़ 65 लाख 85 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को पंचायत भवन तक पहुंचने में सुविधा होगी।

पदोन्नति में हो रही देरी पर केंद्रीय जीएसटी अधीक्षकों ने शुरू किया राष्ट्रव्यापी आंदोलन

- 23 नवंबर से काली पट्टी लगाकर करेंगे काम

रायपुर। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल टैक्स (एआईएएससीटी) ने केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षकों की लंबित सेवा-संबंधी मांगों के समाधान हेतु एआईएएससीटी एवं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है।

सेक्रेटरी जनरल रवीश चंद्र ने बताया कि उचित माध्यम के जरिए व्यक्तिगत अभ्यावेदन जमा करने का क्रम जारी है। 1 नवम्बर से लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार शुरू किया जाएगा। 23-27 नवम्बर को विरोध के प्रतीक के रूप में काली पट्टियाँ पहनकर काम किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसम्बर को देशभर के मुख्यालयों पर भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन एवं गेट मीटिंग आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि मांगों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता और



लंबित मुद्दों के समाधान हेतु ठोस एवं समयबद्ध कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो एसोसिएशन आगे वर्क-टू-रूल, असहयोग आंदोलन, आधिकारिक कार्यों के लिए निजी मोबाइल फोन का उपयोग न करने, आधिकारिक व्हाट्सऐप समूहों से बाहर निकलने तथा धरना जैसे कार्यक्रम भी शुरू करेगी।

दरअसल, कैडर में लंबे समय से पदोन्नति के अवसरों का अभाव है। परिणामस्वरूप, अनेक अधीक्षक लगभग तीन दशकों की सेवा के बाद भी केवल एक पदोन्नति के साथ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस स्थिति में बेहतर कैरियर प्रगति और लंबित मांगों के समयबद्ध समाधान के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक है। एआईएएससीटी की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति (सीईसी) की 12-13 सितंबर को भोपाल में आयोजित बैठक में देशभर से आए प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में पदोन्नति, सेवा शर्तों, कैरियर प्रगति एवं अधिकारियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक प्रस्ताव पारित किए गए।

एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में वर्ष 2014 से आगे की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूचियों को शीघ्र अंतिम रूप देकर जारी करना तथा सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु लंबित डीपीसी की कार्यवाही पूरी करना शामिल है। बार-बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद पात्र अधिकारी पदोन्नति की प्रतीक्षा में अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। एआईएएससीटी व्यापक कैडर पुनर्गठन की मांग कर रहा है, ताकि कैरियर में ठहराव दूर हो और पदोन्नति के अवसर बढ़ें। पिछला पुनर्गठन वर्ष 2014 में हुआ था, जिसकी समीक्षा हर पाँच वर्ष में अपेक्षित थी। लेकिन एक दशक से अधिक समय बीतने के बावजूद कोई नया पुनर्गठन नहीं हुआ है। एसोसिएशन ने कैडरों के बीच पदोन्नति संबंधी असमानता दूर करने हेतु तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

- छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: पहले दिन उमड़ी आगंतुकों की भीड़

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव 2026 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का विभागीय स्टॉल नागरिकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राज्योत्सव के पहले दिन मंडल के स्टॉल पर बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंचे और विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं, उपलब्ध मकानों तथा आवासीय परियोजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्रदेश के नागरिकों को किफायती, गुणवत्तापूर्ण एवं सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराने की दिशा में मंडल द्वारा किए जा रहे प्रयासों और संचालित योजनाओं के प्रति लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

राज्योत्सव परिसर में मंडल का विभागीय स्टॉल डोम एच1 के स्टॉल क्रमांक 11 पर स्थापित किया गया है।



यहां मंडल की विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं, उपलब्ध संपत्तियों तथा नागरिक सुविधाओं की जानकारी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। स्टॉल पर पहुंचने वाले नागरिक अपनी आवश्यकता, बजट एवं पसंद के अनुरूप उपलब्ध आवासीय विकल्पों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

राज्योत्सव के पहले दिन मंडल के स्टॉल पर पहुंचे आगंतुकों ने विभिन्न जिलों में संचालित आवासीय योजनाओं और उपलब्ध मकानों के संबंध में विशेष रुचि दिखाई। नागरिकों ने आवासों की उपलब्धता, स्थान, कीमत, बुकिंग प्रक्रिया तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। स्टॉल पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आगंतुकों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से नागरिकों को विभिन्न आवासीय विकल्पों के बारे में समझने और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने में सुविधा मिल रही है। विशेष रूप से स्वयं का घर खरीदने के इच्छुक नागरिकों के लिए यह स्टॉल उपयोगी जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विस्तार के साथ अधोसंरचना विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

5 नवंबर को सीएचओ का प्रदेशव्यापी आंदोलन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय का करेंगे घेराव

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी 5 नवंबर को स्वास्थ्य भवन नवा रायपुर स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय का घेराव करेंगे। लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने, इंसेंटिव घोटाले के नाम पर केवल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को निशाना बनाकर कथित द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने, कार्यों के अत्यधिक बोझ, अस्पष्ट कार्य-दायित्वों तथा विभिन्न जिलों में नौकरी से निकालने की धमकियों के विरोध में यह प्रदेशव्यापी आंदोलन आयोजित किया जाएगा।

संघ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को केवल अपनी प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए विगत 3-4 वर्षों से लगातार आंदोलन, ज्ञापन एवं विरोध प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रोत्साहन राशि का भुगतान शासन एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह



समय पर होना चाहिए, उसके लिए कर्मचारियों को बार-बार सड़क पर उतरने विवश होना पड़ रहा है। संघ के अनुसार, राज्य कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष एवं समय-समय पर प्रोत्साहन राशि के सत्यापन और भुगतान के लिए स्पष्ट निर्देश एवं आदेश जारी किए जाते हैं। यहां तक कि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पीएलपी पोर्टल के माध्यम से सत्यापन कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद जिला एवं ब्लॉक स्तर के जिम्मेदार अधिकारी राज्य कार्यालय के आदेशों का गंभीरता से पालन नहीं करते। भुगतान एवं सत्यापन में महीनों की देरी तथा पोर्टल संबंधी अनियमितताएं लगातार बनी हुई है। ऐसी स्थिति में राज्य कार्यालय के आदेशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होना प्रदेश की एक गंभीर प्रशासनिक चुनौती बन चुका है। उच्च कार्यालय के निर्देशों की बार-बार अनदेखी से ऐसा प्रतीत होता है कि जिला एवं ब्लॉक स्तर पर इन आदेशों की कोई जवाबदेही ही निर्धारित नहीं है।

संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि इंसेंटिव घोटाले के नाम पर जारी आदेशों एवं जांच संबंधी कार्रवाई में केवल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को लक्षित किया जा रहा है, जबकि प्रोत्साहन राशि संस्थागत प्रदर्शन एवं उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर के विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर आधारित होती है। ऐसी स्थिति में यदि अनियमितता की जांच की जानी है तो संबंधित संस्था के सभी कर्मचारियों की भूमिका, कार्य-विभाजन एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी एक संवर्ग को चुनकर कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं है।

इसके अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्वीकृत मानव संसाधन की उपलब्धता एवं कार्य-विभाजन की स्थिति की अनदेखी करते हुए संपूर्ण संस्थागत कार्यों, ऑनलाइन प्रविष्टियों एवं विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अतिरिक्त भार केवल सीएचओ पर डाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कई जिलों में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नौकरी से निकालने की धमकियां दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। इससे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों में असुरक्षा एवं असंतोष का वातावरण निर्मित हो रहा है।

संघ की प्रमुख पांच सूत्रीय मांगें

1. इंसेंटिव घोटाले के नाम पर केवल सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के विरुद्ध जारी द्वेषपूर्ण एवं अनुचित आदेश को तत्काल निरस्त/संशोधित किया जाए तथा विगत 7-8 माह की लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

2. प्रोत्साहन राशि भुगतान में लगातार हो रही अनियमितताओं एवं अव्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के मूल वेतन में समायोजित किया जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर पदस्थ समस्त मानव संसाधन के अस्पष्ट कार्य-दायित्वों का पुनरीक्षण कर प्रत्येक पद के अनुरूप स्पष्ट एवं न्यायसंगत कार्य-विभाजन सुनिश्चित किया जाए।

न्यायालय नायब तहसीलदार रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
// ईश्तहार //
/31-6/2026-2027 रा.प्र.क्रमांक /
ग्राम भाठागांव प.ह.नं.- 60.
रायपुर दिनांक 27/10/2026
तहसील व जिला रायपुर

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शशिकांत गायकवाड़ पिता योगीराज गायकवाड निवासी-ए-41 राधास्वामी नगर, भाठागांव चौक के पास रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा इसे न्यायालय में मू-राजस्व सहिता 1959 की धारा 109/110 फौती नामांतरण हेतु आवेदन पत्र पेश कर लेख किया है कि आवेदक की पत्नी स्व. श्रीमती मंजू गायकवाड़ पति शशीकांत गायकवाड़ के हक स्वामित्व की भूमि वाके मौजा ग्राम भाठागांव प.ह.न.60 रा.नि.मं रायपुर 1. तहसील व जिला रायपुर स्थित (छ.ग.) स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 619/10 रकबा 0.0220 हेक्टेयर है। आवेदक की पत्नी स्व. श्रीमती मंजू गायकवाड़ की मृत्यु दिनांक 20/08/2024 को हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। मृतक स्व. श्रीमती मंजू गायकवाड़ के विधिक वारिसान 1. शशिकांत गायकवाड़ पिता योगीराज गायकवाड़ (पति) 2. अनुराग गायकवाड़ (पुत्र) 3. वरूण गायकवाड़ (पुत्र) पिसरान शशिकांत गायकवाड़ है, इनके अलावा कोई अन्य विधिक वारिसान नहीं है। राजस्व अभिलेख से आवेदक की पत्नी स्व. श्रीमती मजू गायकवाड़ का नाम विलोपित कर उनकी फौती उठाकर विधिक वारिसानों का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है। उक्त प्रकरण की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 19/11/2026 को अंगी

अतएव जिस किसी व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मय दस्तावेज अपनी लिखित दावा / आपत्ति दिनांक 19/11/2026 को इस न्यायालय में पेश करें। नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

किया गया। आज दिनांक 27/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी

नायब तहसीलदारार

जन महाभियोग से नहीं हिलेगी संवैधानिक कुर्सी

कांतिलाल मांडोत

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से आयोजित जन महाभियोग कार्यक्रम ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 31 अक्टूबर 2026 को आयोजित इस सांकेतिक संसद में 19 विपक्षी दलों के नेताओं और सांसदों ने हिस्सा लिया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में चली इस मॉक संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जन महाभियोग का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष के कई प्रमुख नेता इस आयोजन में मौजूद रहे। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम बताया, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से इस आयोजन का कोई प्रत्यक्ष कानूनी प्रभाव नहीं है। दरअसल, लोकतंत्र में विरोध करना, सवाल उठाना और संवैधानिक संस्थाओं से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है। लेकिन किसी संवैधानिक पदाधिकारी को हटाने के लिए राजनीतिक सहमति और संवैधानिक प्रक्रिया के बीच अंतर समझना भी उतना ही आवश्यक है। विपक्ष का यह आयोजन जनता के बीच चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं पहुंचाने का प्रयास है। इसे राजनीतिक रूप से एकजुटता दिखाने और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा सकता है। मगर किसी आवास पर आयोजित सांकेतिक संसद में प्रस्ताव पारित होने से वास्तविक संसद की संवैधानिक शक्तियां स्थानांतरित नहीं हो जातीं। भारत का संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इसी अनुच्छेद के खंड पांच में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और आधार निर्धारित किए गए हैं। अर्थात उन्हें केवल सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर संसद की निर्धारित विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। यह सुरक्षा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए है। इसलिए जन महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना और संवैधानिक रूप से किसी पदाधिकारी को हटाना दो अलग-अलग बातें हैं। विपक्ष का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूचियों से नाम हटाने में पारदर्शिता नहीं बरती गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लगभग 40 लाख नए मतदाता जोड़ने और एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाने का मुद्दा भी उठाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल किया कि यदि मृत और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं तो आयोग को यह बताने में संकोच क्यों होना चाहिए कि कितने नाम हटाए गए और किन कारणों से हटाए गए? यह सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्व रखता है। मतदाता सूची की शुद्धता जितनी जरूरी है, उसकी पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। राहुल गांधी ने इस आयोजन को राजनीतिक हथियार बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं के पर्याप्त प्रमाण हैं। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग से कई बार जानकारी मांगी गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। विपक्ष ने राष्ट्रपति से मुलाकात, मार्च और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जैसे रास्ते अपनाने का भी दावा किया है। हालांकि इन आरोपों की सत्यता का निर्धारण राजनीतिक भाषणों से नहीं, बल्कि दस्तावेजों, तथ्यों और निष्पक्ष जांच से ही होना चाहिए।

विधान परिषद चुनाव : भाजपा के 'अभेद्य किलों' में कैसी सेंध?

किशन सनमुखदास भावनानी



वैश्विक स्तरपर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,जहां चुनाव केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं, असंतोष, विश्वास और परिवर्तन की इच्छा को व्यक्त करने का संवैधानिक माध्यम भी हैं। यहां लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में आम मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं,जबकि विधान परिषद की कुछ सीटों पर शिक्षक,स्नातक स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य जैसे अलग-अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है।राज्यसभा के माध्यमसे राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद के उच्च सदन में होता है। मैं बताना चाहूंगा कि इस बहुस्तरीय व्यवस्था का मूल उद्देश्य यही है कि लोकतंत्र में केवल संख्या ही नहीं,बल्कि विभिन्न सामाजिक,शैक्षणिक और संस्थागत अनुभवों की आवाज़ भी सुना जाए।दिनांक 29 अक्टूबर 2026 को शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से आए नतीज़ो का विशेष महत्व इसलिए है कि इनमें मतदाता बनने के लिए निर्धारित पात्रता और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ऐसे मतदाताओं से शिक्षा,रोजगार, प्रशासन, सार्वजनिक सेवाओं और विकास संबंधी मुद्दों पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है।हालांकि,किसी मतदाता की शैक्षणिक योग्यता अपने आप में उसके राजनीतिक विवेक की गारंटी नहीं होती;लोकतंत्र की असली ताक़त स्वतंत्र निर्णय,जागरूकता और निष्पक्ष मतदान में सटीकता से निहित है।

साथियों बात अगर हम 23 अक्टूबर का मतदान,29 अक्टूबर2026 को आए नतीजों की चर्चा कर इसको समझने की करें तो,23 अक्टूबर 2026 को चार राज्यों उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए मतदान हुआ।इन चुनावों में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे तथा मतदान मतपत्रों के माध्यम से कराया गया।मतगणना कई जगह लंबी चली और 29 अक्टूबर को सामने आए नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में जगह बना ली। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार,28 सीटों में भाजपा ने 13 सीटें जीतीं,जबकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत की और जन सुराज पार्टी ने बिहार में विधान परिषद में अपना खाता खोला।इस चुनाव में एनडीए के कुल 16 सीटें जीतने का आंकड़ा भी राजनीतिक चर्चा में सामने आया है,लेकिन भाजपा और उसके सहयोगियों के परिणामों को अलग- अलग समझना आवश्यक है।सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न केवल यह नहीं है कि किस गठबंधन नेकितनी सीटें जीतीं,बल्कि यह भी है कि किन क्षेत्रों में मतदाताओं ने स्थापित राजनीतिक समीकरणों से अलग फैसला सुनाया।

साथियों, मेरे लिए भी यह चुनाव व्यक्तिगत रूप से लोकतांत्रिक सहभागिता का अनुभव रहा,क्योंकि मैंने 23 अक्टूबर 2026 को स्नातक मतदाता निर्वाचन क्षेत्र से अपने मताधिकार का प्रयोग किया।मतदान केंद्र पर अन्य मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी देखकर यह महसूस हुआ कि लोकतंत्र में प्रत्येक मत का अपना महत्व है।शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने वाला प्रत्येक नागरिक अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उम्मीदवार का चयन करता है।इसलिए इन नतीजों को केवल राजनीतिक दलों की जीत-हार के चश्मे से नहीं,बल्कि मतदाता की अपेक्षाओं, स्थानीय समस्याओं, उम्मीदवार की पहुंच और संगठनात्मक सक्रियता के संदर्भ में भी सटिका से देखना चाहिए द्य

साथियों बात अगर हम कांग्रेस नेत्री का वायरल वीडियो और 'गढ़ ध्वस्त' होने का दावा इसको समझने की करें तो 29 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर कांग्रेस की एक नेत्री और प्रवक्ता का वीडियो चर्चा में आया,जिसमें भाजपा की हार को लेकर तीखी राजनीतिक टिप्पणी की गई।वीडियो में कथित तौर पर कहा गया कि बैलेट से चुनाव होने पर भाजपा के गढ़ ढह गए और बड़े नेताओं के क्षेत्रों में पार्टी को झटके लगे। इस बयान को विपक्ष की राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखना उचित होगा, न कि पूरे चुनाव का निष्पक्ष निष्कर्ष मान लेना। चुनाव परिणामों की व्याख्या में विपक्ष अपनी बात रखेगा और सत्तारूढ़ दल अपनी उपलब्धियों तथा जीती गई सीटों को सामने रखेगा। लोकतांत्रिक विमर्श में दोनों पक्षों के दावों को वास्तविक परिणामों और निर्वाचन क्षेत्र के आंकड़ों की कसौटी पर परखना आवश्यक है।मतपत्रों से मतदान होना अपने आप में किसी दल की हार या जीत का कारण सिद्ध नहीं करता; मतदान प्रणाली और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ठोस प्रमाण चाहिए।इस चुनाव का वास्तविक संदेश स्थानीय स्तर पर मतदाताओं के बदलते रुझान, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और राजनीतिक दलों की जमीनी तैयारी में तलाशना अधिक सार्थक होगा।

साथियों बात अगर हम वाराणसी - प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सपा की सफलता का राजनीतिक अर्थ को समझने की करें तो, वाराणसी का परिणाम इसलिए विशेष चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री इसी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं,इसलिए यहां के विधान परिषद चुनावों को राजनीतिक दल अपने संगठन और स्थानीय जनाधार की स्थिति समझने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी की शिक्षक और स्नातक,दोनों सीटों पर सफलता हासिल की।उत्तर प्रदेश की घोषित सीटों के परिणामों में भाजपा ने छह और सपा ने पांच सीटें जीतीं।यह नतीजा भाजपा के लिए स्थानीय स्तर पर आत्ममंथन का विषय हो सकता है, लेकिन इसे प्रधानमंत्री के प्रति पूरे देश के मतदाताओं के रुख का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा।वाराणसी संभाग के राजनीतिक महत्व को समझने के लिए इसके आठ जिलों वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र, की सामाजिक एवं राजनीतिक विविधता पर ध्यान देना होगा।इन जिलों में जातीय समीकरण स्थानीय नेतृत्व, शिक्षकों की समस्याएं,रोजगार शिक्षा व्यवस्था, ग्रामीण विकास और सरकारी सेवाओं से जुड़ी अपेक्षाएं अलग- अलग प्रभाव डाल सकती हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बढ़त मिली थी, लेकिन विधान परिषद के चुनावों में मतदाता समूह सीमित और अलग पात्रता वाला होता है।इसलिए शिक्षक और स्नातक मतदाताओं का फैसला आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे क्षेत्र की जनता के मतदान व्यवहार का सीधा प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता।फिर भी, दोनों वाराणसी सीटों पर सपा की सफलता भाजपा के स्थानीय संगठन के लिए यह विचार करने का अवसर है कि क्या उम्मीदवारों के चयन, मतदाताओं से संपर्क और पेशेवर वर्गों की समस्याओं पर सटिका से पर्याप्त ध्यान दिया गया था। साथियों बात अगर हम नागपुर- संघ मुख्यालय मुख्यमंत्री व केंद्रीय परिवहन मंत्री का गृहछेत्र और भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्र में कांग्रेस की जीत को समझने की करें तो, महाराष्ट्र का नागपुर राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है और यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र भी है।ऐसे क्षेत्र में स्नातक निर्वाचन सीट पर कांग्रेस के अभिजीत वंजारी की जीत ने परिणामों को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया।वंजारी ने भाजपा के सुधाकर कोहले को कुल 3,271 मतों से पराजित किया।उन्हें 67,231 मत मिले,जबकि कोहले को 63,960 मत प्राप्त हुए ऐसी जानकारी मीडिया से प्राप्त हुई।इस मुकाबले की एक विशेषता मतगणना की प्रक्रिया भी रही। प्रथम वरीयता के मतों में भाजपा उम्मीदवार को बढ़त मिली थी,लेकिन आवश्यक मत- कोटा पूरा नहीं होने के कारण अगली वरीयताओं के मतों की गणना की गई और अंतिम परिणाम बदल गया। इससे स्पष्ट होता है कि विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतपत्रों पर वरीयता क्रम का कितना महत्व हो सकता है।इस जीत को केवल किसी दल के गढ़ में सेंध लगने के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह भी समझना जरूरी है कि स्नातक मतदाताओं के बीच उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान,पूर्व कार्य,स्थानीय संपर्क और स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिले मतों का अंतिम परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है।नागपुर में कांग्रेस की सफ़लता भाजपा के लिए संगठनात्मक समीक्षा का विषय अवश्य है,लेकिन इससे संघ के प्रभाव या पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति के समाप्त होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। साथियों बात अगर हम पटना- पांच बार के एमएलसी नवल किशोर यादव की हार के संदेश को समझने की करें तो, बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम भी महत्वपूर्ण रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पांच बार विधान परिषद सदस्य रह चुके नवल किशोर यादव को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह ने पराजित किया। उपलब्ध परिणाम विवरण के अनुसार, डॉ.संजीव को 4,487 मत और नवल किशोर यादव को 3,430 मत मिले, अर्थात जीत का अंतर 1,057 मत रहा, ऐसी जानकारी मीडिया से आई लगातार चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधि की हार यह याद दिलातीहै कि राजनीतिक अनुभव और पुराना जनाधार अपने आप में भविष्य की जीत सुनिश्चित नहीं करते। शिक्षक मतदाताओं की अपेक्षाएं,शिक्षा संस्थानों की समस्याएं,सेवा-संबंधी मुद्दे, उम्मीदवार की उपलब्धता और स्थानीय संगठन की सक्रियता परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

22. नागार्जुन का शून्यवाद



गतांक से आगे...

और न उन पदार्थों को असन् ही कह सकते हैं, क्योंकि यदि असत् होना ही उनका स्वभाव ही है तो कारकों का व्यापार व्यर्थ है, क्योंकि वे अपने असत् स्वभाव को तो छोड़ ही नहीं सकते, और न पदार्थों का स्वभाव सत् और असत् उभयात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है, और न पदार्थों का स्वरूप अनुभयात्मक अर्थात् सत् और असत् दोनों से भिन्न कहा जा सकता है क्योंकि उसमें भी परस्पर विरोध है। इस प्रकार (i) सत् (ii) असत् (iii) सदसत् (iv) न सत् न असत, इन चारों कोटियों से भिन्न (चतुष्कोटिविनिर्मुक्त) पदार्थों का स्वभाव शून्य रूप है।

बौद्ध दर्शन के इतिहास की पृष्ठभूमि में यदि इस सिद्धान्त को रखखें तो स्पष्ट हो जायगा कि हीनयान के दोनों प्रमुख सम्प्रदायों ने थेरावाद और सर्वास्तिवाद ने - द्रव्य, अवयवी या आत्मा (जिसके लिये बौद्ध शब्द पुद्गल है) का निषेध कर प्रत्येक क्षण आविर्भूत होने वाले धर्मों की अनन्तता (plurality) मानी थी। उसके अनुसार यद्यपि आत्मा, द्रव्य, अवयवी या पुद्गल असत् है परन्तु क्षणिक धर्म सत् हैं, यथार्थ (real) हैं। परन्तु शून्यवाद एक पग आगे जाता है, वह कहता है धर्म भी वस्तुत: असत् ही हैं। शून्यवाद अकाट्य तर्कों से स्थापित करता है कि कारण द्रव्य आदि का कोई भी विचार बुद्धि से परीक्षा करने पर ठहरता ही नहीं। महायान के आधार ग्रन्थ लङ्कावतार में कहा है कि ज्यों-ज्यों बस्तुओं पर विचार करते हैं उनका तत्त्व उड़ता जाता है। हीनयान के दर्शन ने अनात्मवाद और अद्रव्यवाद की स्थापना की। महायान के दर्शन शून्यवाद ने धर्मनैरात्म्य या धर्मशून्यता की स्थापना की। कारणवाद के क्षेत्र में हीनयान ने वैदिक दार्शनिक सम्प्रदायों के कारणवाद का निराकरण किया था।

क्रमश:... ...

पतिव्रता से पराजित हुए इंद्र और कामदेव, सुकला के अटूट सतीत्व की रक्षा कैसे हुई?

आशुतोष गर्ग



कृकल नामक वैश्य की पत्नी पतिव्रता थी। उसका नाम सुकला था। उसके अटूट सतीत्व की ख्याति देवराज इंद्र तक पहुंची, तो एक दिन इंद्र ने निश्चय किया कि वह सुकला को धर्म के मार्ग से विचलित करेंगे। उन्होंने कामदेव को बुलाकर कहा कि वह पतिव्रता सुकला को अपने प्रभाव में लाने में उनकी सहायता करे। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ उपस्थित हुए और गर्व से बोले, 'देवराज! मैंने अनेक देवताओं, ऋषियों और तपस्वियों को अपने बाणों से विचलित किया है। फिर एक साधारण स्त्री को वश में करना कौन-सी कठिन बात है? मैं सुकला के सतीत्व को नष्ट कर दूंगा।'

इंद्र ने एक सुंदर और गुणवान पुरुष का रूप धारण किया और एक दूती को सुकला के पास भेजा। उस दूती ने पहले तो सुकला के सौंदर्य की प्रशंसा की, फिर उसके पति के विरुद्ध बातें करते हुए कहा कि कृकल उसे अकेला छोड़कर स्वयं तीर्थयात्रा पर गए हैं। उसने सुकला से कहा कि पति ही पत्नी की चिंता नहीं करेगा, तो उसके लिए जीवनभर प्रतीक्षा क्यों करनी? वह बोली कि युवावस्था क्षणभंगुर है और मनुष्य को समय रहते समस्त सुखों का आनंद लेना चाहिए। उसने इंद्र के रूप में उपस्थित उस पुरुष को सर्वगुणसंपन्न बताते हुए सुकला को उसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया।

यह सुनकर सुकला बोली, 'यह शरीर मल-मूत्र से भरा हुआ, नश्वर और क्षणभंगुर है। इसकी सुंदरता पर गर्व करना व्यर्थ है, क्योंकि समय के साथ यह रूप नष्ट हो जाता है। संसार में किसी का शरीर दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। आत्मा तो दिव्य, शुद्ध और रूपरहित है, जो सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। फिर, केवल शरीर के आकर्षण के कारण मैं अपने धर्म से कैसे विमुख हो सकती हूं? इंद्रिय-सुख क्षणिक हैं और उसके समाप्त होते ही मनुष्य फिर उसी असंतोष में लौट आता है। इसलिए, मैं किसी अन्य पुरुष को स्वीकार नहीं कर सकती।'

सुकला का तर्क सुनकर दूती लौट आई और उसने इंद्र को सुकला का उत्तर सुनाया। उसके ज्ञान और दृढ़ता से प्रभावित होकर इंद्र ने भी माना कि ऐसी पवित्र स्त्री को विचलित करना सरल नहीं होगा।

परंतु, कामदेव को अपने सामर्थ्य पर अभिमान था। वह इंद्र, रति और अपनी सहचरी क्रीड़ा के साथ सुकला को परास्त करने के लिए चल पड़ा।

उधर सत्य ने धर्म से कहा कि कामदेव का यह प्रयास उन सभी सद्गुणों को नष्ट करने का प्रयत्न है, जिनके कारण संसार में धर्म और पुण्य की स्थापना होती है। धर्म ने आश्वासन दिया कि वह सुकला की रक्षा के लिए उचित उपाय करेगा। धर्म की प्रेरणा से प्रज्ञा, पक्षी का रूप धारण कर सुकला के घर पहुंची और उसे यह शुभ समाचार सुनाया कि उसका पति सात दिनों के भीतर घर लौट आएगा। यह सुनकर सुकला बहुत प्रसन्न हुई। इसी बीच क्रीड़ा ने एक दुखी स्त्री का रूप धारण कर उससे मित्रता कर ली और उसे पुण्य-संचय के बहाने एक सुंदर वन में ले गई। वहां कामदेव इंद्र के शरीर में प्रवेश करके अपने पांच पुष्पबाण चलाने के लिए तैयार बैठा था। रति और प्रीति ने भी सुकला को मोहित करने का प्रयास किया, पर सुकला ने कहा, 'जहां मेरे पति हैं, वहीं मेरा मन है। मेरा वास्तविक अस्तित्व अपने पति के प्रति समर्पण में है।'

इजराइल में अरब पार्टियां बनेगी सत्ता की धुरी

राज कुमार सिन्हा



इजराइल के हालिया आम चुनावों के अंतिम नतीजों के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके दक्षिणपंथी गठबंधन को 120 सदस्यीय संसद में 53 सीटें हासिल हुई हैं। विपक्षी गठबंधन के गादी आइजेनकोट के नेतृत्व को 48 सीटें मिली हैं, जबकि अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने 19 सीटें हासिल की हैं। सरकार बनाने के लिए संसद में 61 सीटों का बहुमत आवश्यक है। अरब नेतृत्व वाली पार्टियों की 19 सीटें पिछले चुनावों की तुलना में लगभग दोगुनी है। अरब मतदाताओं ने नेतन्याहू सरकार और उसकी नीतियों के विरोध में एकजुट होकर मतदान किया, जिससे इजराइल का पारंपरिक दक्षिणपंथी राजनीतिक समीकरण बिगड़ गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों और उसके बाद गाजा, लेबनान तथा ईरान से जुड़े क्षेत्रीय संघर्षों के बाद यह पहला चुनाव था।

लंबे समय से चल रहे युद्ध, गहराते अंतरराष्ट्रीय अलगाव और सुरक्षा चूकों को लेकर जनता में उपजी थकान ने नेतन्याहू के खिलाफ माहौल को प्रभावित किया है। नेतन्याहू पर वर्षों से भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। यदि वे सत्ता से बाहर होते हैं या बहुमत जुटाने में नाकाम रहते हैं, तो उनके खिलाफ चल रहे मामलों और 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलताओं की जांच का दायरा और कड़ा हो सकता है। नेतन्याहू के 53 सीटों वाले गुट और विपक्ष के 48 सीटों वाले गुट को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में 19 सीटों वाली अरब पार्टियां पूरे राजनीतिक गणित में किंगमेकर की भूमिका में आ गई है। हालांकि, यहूदी दक्षिणपंथी दलों और विपक्षी गुट के कुछ सदस्यों के बीच अरब पार्टियों के साथ औपचारिक गठबंधन को लेकर तीखा वैचारिक विरोध है, जिससे सरकार बनाना बेहद पेचीदा हो गया है। सरकार गठन के लिए विभिन्न दलों के बीच मोलभाव और हफ्तों या महीनों तक राजनीतिक गतिरोध रहने की आशंका है।

विकल्प के तौर पर अल्पमत सरकार बनाने या दलबदल के जरिए सांसदों को अपने पक्ष में करने की कोशिशें की जा सकती है। चुनाव के आधिकारिक नतीजे 4 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति को सौंपे जाने हैं। यदि कोई औपचारिक गठबंधन नहीं बनता है, तो नेतन्याहू बाहरी समर्थन अथवा कुछ सांसदों के मतदान के दौरान सदन से बाहर रहने के भरोसे एक कमजोर अल्पमत सरकार बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि सभी पक्ष कानूनी रूप से निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार बनाने के लिए किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इजराइल में नए चुनाव कराने पड़ सकते हैं। इसके चलते सभी राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए और अधिक सहयोगियों की तलाश करनी होगी। लेकिन राजनीति और विचारधारा को लेकर गहरे मतभेद गठबंधन समझौते तक पहुंचना आसान नहीं बनाते।

सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हटाने के लिए विपक्ष का सबसे व्यावहारिक विकल्प इजराइल में अरबों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन बनाना है। लेकिन इसी बीच दो दक्षिणपंथी विपक्षी नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और पूर्व रक्षा मंत्री एविग्डोर लिबरमैन ने इस योजना का कड़ा विरोध किया है। एक अन्य संभावना यह है कि दोनों मौजूदा राजनीतिक गुटों की पार्टियां आपसी टकराव जारी रखने के बजाय एकजुट होकर एकता सरकार का गठन करें। इस योजना के तहत नेतन्याहू की लिकुड पार्टी अपने मौजूदा सहयोगियों और कम से कम एक विपक्षी पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जुटाने का प्रयास करेगी। इसकी सबसे बड़ी बाधा यह है कि आइजेनकोट ने घोषणा कर दी है कि वह नेतन्याहू के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। यदि वह अपना रुख बदलते हैं, तो उन्हें उन मतदाताओं का समर्थन खोने का खतरा है जो नेतन्याहू के शासन का अंत चाहते हैं। गादी आइजेनकोट, नफ्ताली बेनेट, एविग्डोर लिबरमैन और यायर गोलान सहित सभी चार विपक्षी दलों के नेताओं ने भी घोषणा की है कि वे नेतन्याहू के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इस बीच, नेतन्याहू के गुट को संसद में बहुमत हासिल करने के लिए अभी भी आठ सीटों की कमी है। इसलिए विपक्ष के आठ सांसदों को पाला बदलने के लिए राजी करना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है।

खबर है कि नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल 7 सीटों वाली यूनाइटेड तोरा यहूदी (यूटीजे) पार्टी ने गादी आइजेनकोट के विपक्षी गठबंधन को समर्थन देने का और विश्वास मत से गैरहाजिर रहने का प्रस्ताव रखा है। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग संसद में सीटें जीतने वाली पार्टियों के नेताओं के साथ सार्वजनिक परामर्श करेंगे। विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रपति एक सांसद का चयन करेंगे, जिन्हें नई सरकार बनाने का कार्य सौंपा जाएगा। चूंकि अरब दलों द्वारा आइजेनकोट का समर्थन किए जाने की संभावना है, इसलिए येशर पार्टी के नेता को यह अवसर सबसे पहले दिया जा सकता है।नियमों के अनुसार, सरकार बनाने के लिए नियुक्त व्यक्ति को 28 दिन का समय मिलेगा और उसे 14 दिनों तक का विस्तार दिया जा सकता है। यदि पहला उम्मीदवार असफल हो जाता है, तो राष्ट्रपति यह कार्य किसी अन्य सांसद को सौंप सकते हैं। इस व्यक्ति को संसद में पर्याप्त समर्थन जुटाने के लिए 28 दिन का समय मिलेगा। यदि अन्य सभी विकल्प विफल हो जाते हैं, तो इजराइल को नए चुनाव कराने पड़ सकते हैं।

इस चुनाव के परिणामों ने इजराइल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया है। लंबे समय से देश की राजनीति में प्रभावशाली रहे दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी समीकरण को पहली बार इतनी गंभीर चुनौती मिली है। अरब पार्टियों की बढ़ी हुई सीटें केवल चुनावी सफलता नहीं हैं, बल्कि यह इजराइल के भीतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकारों और सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष का भी संकेत देती हैं। आने वाले समय में इजराइल की राजनीति मुख्य रूप से तीन संभावनाओं के इर्द-गिर्द घूम सकती है। पहली संभावना यह है कि विपक्षी दल अरब पार्टियों के समर्थन से नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के लिए साझा मोर्चा बनाएं। ऐसा होने पर इजराइल में पहली बार अरब राजनीतिक दलों की भूमिका सरकार गठन में निर्णायक स्तर तक पहुंच सकती है। इससे देश की राजनीति में यहूदी और अरब नागरिकों के बीच राजनीतिक सहभागिता का नया अध्याय शुरू हो सकता है। दूसरी संभावना एक कमजोर गठबंधन अथवा राष्ट्रीय एकता सरकार की है। यदि नेतन्याहू के विरोधी और कुछ दक्षिणपंथी दल किसी साझा कार्यक्रम पर सहमत होते हैं, तो सरकार का गठन संभव हो सकता है। लेकिन ऐसी सरकार में विदेश नीति, फिलिस्तीन के सवाल, गाजा युद्ध, सुरक्षा नीति और न्यायिक सुधार जैसे मुद्दों पर गंभीर मतभेद बने रहेंगे। इसलिए उसका स्थायित्व भी एक बड़ी चुनौती होगा। तीसरी संभावना यह है कि कोई भी राजनीतिक गुट बहुमत हासिल नहीं कर पाए और इजराइल को फिर से चुनाव की ओर जाना पड़े।

ऐसी स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। बार-बार चुनाव होने से न केवल शासन व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि युद्ध, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी अनिश्चितता के घेरे में आ सकती है। इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू नेतन्याहू का व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य भी है। भ्रष्टाचार के मुकदमे, 7 अक्टूबर 2023 की सुरक्षा विफलताओं की जवाबदेही और लंबे युद्ध को लेकर उठ रहे सवाल उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए चुनौती बने हुए हैं। सत्ता से बाहर होने की स्थिति में उनके खिलाफ जांच और राजनीतिक जवाबदेही की मांग और तेज हो सकती है। दूसरी ओर, यदि वे किसी तरह सत्ता में वापसी करते हैं, तो उन्हें पहले की तुलना में अधिक सीमित राजनीतिक समर्थन के साथ सरकार चलानी पड़ सकती है। इजराइल की भावी राजनीति का प्रभाव केवल देश की आंतरिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा।

आज का इतिहास

1762 ब्रिटेन और स्पेन के बीच पेरिस की संधि हुई।
1796 जॉन एडम्स अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गये।
1869 कनाडा में हैमिल्टन फुटबॉल क्लब अस्तित्व में आया।
1903 पनामा को कोलंबिया से आजादी मिली।
1938 'असम हिन्दी प्रचार समिति' नामक एक संस्था कायम की गई।
1948 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया।
1958 तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया।
1962 चीन के हमले के मद्देनजर भारत में गोल्ड बॉन्ड स्कीम की घोषणा की गयी।
1984 भारत में सिख विरोधी दंगों में तीन हजार से ज्यादा लोग मारे गए।
1988 वायु सेना ने आगरा से एक पैराशूट बटालियन समूह को लिया।
1988 भारतीय सशस्त्र सेना ने मालदीव में हुए एक सैन्य विद्रोह को दबाने में वहाँ की सरकार की सहायता के लिए एक अभियान शुरू किया।
1997 जी-15 समूह का सातवां शिखर सम्मेलन कुआलालम्पुर में प्रारम्भ।
2000 भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिये शुरू की गयी।
2001 अमेरिका ने लश्कर व जैश-ए-मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाया।
2002 नखोम पाथोम की बैठक में लिट्टे ने राजनीति की मुख्य धारा में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की।
2003 पाकिस्तान और चीन के बीच बीजिंग में आठ समझौतों पर हस्ताक्षर।
2006 भारत बेल्जियम के साथ सामाजिक सुरक्षा गारंटी पर समझौता हुआ।
2007 पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की प्रमुख बेनजीर भुट्टो को उनके घर में नजरबन्द किया गया।
2007 पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने संविधान को रद्द कर और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर आपातकाल की घोषणा की।
2008 यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपनी उधारी दरों में 0.5 प्रतिशत की कमी की।
2011 फ्रांस के कैन्स में जी-20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें यूरोजोन ऋण संकट पर चर्चा की गई।
2014 अमेरिका में आतंकवादी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराये जाने के 13 साल बाद उसी जगह पर एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोला गया।

भाजपा के रणनीतिकारों के सामने कई सवाल छोड़ गया एमएलसी चुनाव!

दीपक कुमार त्यागी

देश के चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक) की 28 विधान परिषद (एमएलसी) सीटों पर चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, सभी राजनीतिक दल व विश्लेषक परिणामों का अध्ययन करके उसके अपने-अपने लाभ-हानि के हिसाब से मायने निकाल रहे हैं। लेकिन इस बार का यह चुनाव कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जिनका जवाब राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों के साथ विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को जल्द से जल्द तलाश ना होगा। क्योंकि भाजपा को अन्य दलों से अलग मानते हुए किसी व्यक्ति या परिवार की जागीर की जगह संगठन को सर्वोपरि मानने वाला राजनीतिक दल माना जाता है और वैसे भी अंदरूनी गुटबाजी से दूर अनुशासन वाली पार्टी मानने का दावा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमेशा सार्वजनिक रूप भी किया जाता है। लेकिन एमएलसी के चुनावों के परिणामों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश की हॉट सीट वाराणसी, लखनऊ व महाराष्ट्र में नागपुर जैसी हाईप्रोफाइल सीट पर हारने के पीछे भाजपा के कुछ राजनेताओं की अति महत्वाकांक्षा व अनुशासन का तार-तार होना बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है। पहले पार्टी के अधिकांश राजनेता व कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से कार्य करते हुए धरातल पर नज़र आते थे, लेकिन लंबे समय से सत्ता का सुख लगातार भोगने के कारण अब पार्टी के कुछ राजनेताओं का अहंकार अपने चरम पर है और वह सत्ता के मद में चूर होकर के जनता को ठेंगा दिखाकर चिढ़ाते हुए पार्टी के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व तक के भी दिशा-निर्देशों की आये दिन अनदेखी करने का कार्य कर रहे हैं।

जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह के दौर की भारतीय जनता पार्टी की पहचान एक ऐसे राजनीतिक दल के रूप में होती है, जिसके कार्यकर्ता व नेता किसी भी स्तर के चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसने तो पार्टी के रणनीतिकारों को जीती हुई व हारी हुई सभी ही सीटों के परिणाम पर विस्तार से विश्लेषण करने के लिए सोचने पर मजबूर कर ही दिया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को योगी सरकार के कार्यों के दम पर चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी उम्मीद है। जिस वक्त में यूपी के विधानसभा चुनाव सर पर हैं उस वक्त में पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार एमएलसी चुनावों में हर सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत का अंतर बढ़ाकर के विपक्षी दलों के जनता की अदालत से पैर उखाड़कर के भाजपा के पक्ष में माहौल बनाना चाहते थे। लेकिन सूत्रों के अनुसार लगातार मीटिंग व ईटिंग के बाद भी कुछ भाजपा नेताओं



की ही चीटिंग के चलते भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का यह दांव जन अदालत में उल्टा हो गया है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को एमएलसी चुनावों की रणभूमि में कुछ सीटों पर हार के रूप में उठाना पड़ा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सीट वाराणसी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की सीट लखनऊ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ नागपुर के एमएलसी सीटों के इन चुनाव परिणामों के बाद अब पार्टी में ही संगठन की रणनीति और प्रत्याशी चयन पर सवाल उठाने की गुपचुप सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो हाईप्रोफाइल सीटों के साथ-साथ बाकी सीटों पर भी जीत का अंतर भाजपा के कुछ अपने ही लोगों का भीतरघात, दावेदारों व अन्य जिम्मेदार लोगों के द्वारा सही ढंग से वोट नहीं बनवाने, प्रत्याशी चयन पर सवाल, संगठन के द्वारा बनाई गई जीत की रणनीति और कुछ अपनों के ही द्वारा चुनाव में की गयी चीटिंग की चीख-चीखकर के स्वयं ही पोल खोलने का कार्य रही है।

ऐसी स्थिति में विचारणीय तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व आये दिन चुनावी रणभूमि के लिए सटीक कारगर रणनीति बनाने के लिए छोटी व बड़ी मीटिंग करते रहते हैं और इन मीटिंग में केंद्रीय व प्रदेश स्तर के नेताओं से लेकर के भाजपा के मंडल स्तर के नेताओं व कार्यकर्ताओं तक की भी मौजूदगी समय-समय पर रहती है, मीटिंग में पार्टी के नेताओं के द्वारा चुनावी रणभूमि के लिए एक चाक-चौबंद रणनीति बनायी जाती है। लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी में अब एक ऐसा लंबा-चौड़ा धड़ा तैयार हो गया है जो मीटिंग के बाद में ईटिंग कर निकलने के बाद से ही गुटबाजी व अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते संगठन सर्वोपरि के भाव का त्याग करके चीटिंग करने में लग जाता है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में सम्पन्न हुए उत्तर प्रदेश के 11 एमएलसी सीटों के चुनाव भी हैं, इन 11 सीटों में भाजपा 6 सीटें और समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हार के साथ-साथ कुछ सीटों पर तो जैसे-तैसे ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। हालांकि चुनाव परिणामों में दस सीटों पर सिटिंग एमएलसी ही दोबारा चुन लिए गए हैं। केवल लखनऊ स्नातक सीट पर ही बड़ा उलटफेर हुआ है, यहां भाजपा के मौजूदा एमएलसी अवनीश कुमार सिंह को सपा की कांति सिंह ने हरा दिया है। वैसे देखें तो वर्ष 2020 में इन सभी 11 सीटों के चुनाव में भाजपा ने छह, समाजवादी पार्टी ने तीन और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं इस बार भाजपा की सीटें तो छह ही रह गई, लेकिन सपा की सीट तीन से बढ़कर के पांच सीट हो गई हैं। चुनावों के यह परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा में अंदरुनी गुटबाजी और भविष्य में चुनावी रणभूमि में कांटे की टक्कर होने का संकेत दे रहे हैं। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने का सपना देख रही भाजपा हाईकमान के लिए एक गहन आत्ममंथन का विषय है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के चुनावी तरकश में हैट्रिक लगाने के लिए जन अदालत में बताने के लिए कानून व्यवस्था में लेकर के बहुत सारे सरकार के शानदार कार्य हैं, लेकिन इन कार्यों पर पार्टी के कुछ शीर्ष राजनेताओं की अंदरूनी खींचतान, जबरदस्त आपसी गुटबाजी व महत्वकांक्षाएं भारी ना पड़े, इसके लिए समय रहते ही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ठोस व प्रभावी उपाय धरातल पर करने होंगे।

यू.पी व पंजाब में रोचक चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा

वकील अहमद

अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। गठबंधन की तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन तय है। सीटों के बंटवारे पर बात जारी है। पंजाब में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के एक बार फिर लम्बे समय के बाद साथ आने की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देख सकते हैं कि भाजपा की योगी सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सफल है। जबकि अन्य क्षेत्रों में खास सफल नहीं है। यही कारण है कि योगी जी उन चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें करनी थीं। इसके लिए वह फिर से चुनाव को हिंदू-मुस्लिम की ओर ले जा रहे हैं। यही कारण है कि वह 80-20 की बात करते हैं तो कभी वह सपा को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। भाजपा ने अपनी जड़ें जमाने के लिए बहुत ड्क्षहदू-मुस्लिम कर लिया अब उसे अपने काम और सद्भावना पर चुनाव लडना चाहिए क्योंकि वोट के लिए लम्बे समय तक देश में 2 समुदायों को एक-दूसरे के प्रति नफरत रखने की प्रवृत्ति नुकसानदेह हो सकती है। और अगर जेन-जी के रवैये और विचारों को देखें तो यह मूर्खता है। चुनाव वाले प्रदेशों के साथ पूरे देश में जनता इस समय महंगाई से त्रस्त है। बेरोजगारी से युवा हताशा में हैं। आम आदमी पेट भरने के लिए जूझ रहा है। भले ही सरकार लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन का झुनझुना थमाए है लेकिन इसके अलावा भी आम आदमी को और भी कुछ चाहिए होता है जो उसे उसकी कमाई में नहीं मिल पा रहा है। युवाओं में आक्रोश बिना वजह नहीं है। इसे समझने की जरूरत है। यह आक्रोश कभी धर्मेंद्र प्रधान और कभी ज्ञानेश कुमार के विरोध के रूप में निकल रहा है लेकिन सरकार युवाओं को समझ नहीं पा रही और युवा भी सरकार को अपनी सही समस्याएं अच्छे से समझा नहीं पा रहे। यही सब बातें इस बार उन प्रदेशों में चुनावी मुद्दा रहेंगी जहां चुनाव होने हैं। पंजाब में तो खैर मुस्लिम वोट का खास प्रभाव नहीं है। वहां किसानों की समस्याओं, नशा, बढ़ते अपराध मुद्दा हो सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल यदि भाजपा के साथ गठबंधन में यहां चुनाव में उतरता है तो किसानों की समस्याएं उनके लिए मुसीबत बन सकती है क्योंकि पंजाब के किसानों में भाजपा की छवि अच्छी नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब में पांच साल से सत्ता में होते हुए भी जनता में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। नशा और अपराधों को रोकने में बुरी तरह विफल रही है। कांग्रेस पंजाब में पूरे दमखम और सूझबूझ से चुनाव लड़े तो संभवतः सफल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने पी.डी.ए. के नारे के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। एक बात जो मुझे अक्सर कचोटती है, मीडिया और स्वयं मुसलमान भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें अक्सर एक दल के साथ जोड़ कर वोट बैंक के रूप में दिखाया जाता है। अखिलेश उत्तर प्रदेश के एक बड़बोले मुस्लिम नेता से मिले तो मीडिया ने कयास लगाना शुरू किया कि असदुद्दीन ओवैसी के डर से मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए अखिलेश आजम खान से मिले। यह मीडिया और अखिलेश की सोच हो सकती है परंतु मुसलमानों की नहीं क्योंकि वे वोट बैंक नहीं वोटर है। अखिलेश यादव को मेहनत बहुत करनी होगी। उनकी पहले ही पांच साल की सरकार के दौरान उन्होंने कुछ अच्छी शुरूआतें की थीं जैसे प्रदेश में 112 की पुलिस सेवा, एम्बुलैंस सेवा और बिजली आपूर्ति में सुधार लेकिन कुछ नेताओं के कारनामों ने सरकार की छवि को उस समय धूमिल किया था। अखिलेश को जनता को आश्वस्त करना होगा कि आगे ऐसा नहीं होगा। दोनों ही प्रदेशों में इस बार चुनाव बहुत रोचक होगा। हर बार की तरह इस बार भी इन चुनावों में जन-मानसिकता कैसी होगी यह महत्वपूर्ण रहेगा। जनता को अपने विवेक के साथ अपने और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर सरकार चुननी है।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: जीत से कहीं अधिक हार का मच रहा शोर

अमिताभ श्रीवास्तव

महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों के चुनाव के बाद राजनेताओं ने इतना शोर मचा दिया है, जैसे राज्य में सत्तापलट हो गया हो। परिणामों पर वरिष्ठ नेता समझदारी का परिचय देकर कुछ कहने से बचे, लेकिन निचले स्तर के नेता सिर फुटौवल के लिए तैयार हैं। महाविकास आघाड़ी पुणे में अपनी एक सीट गंवाकर और छत्रपति संभाजीनगर की सीट जीत कर फूल गई है, वहीं पुणे में एक नई सीट जीतकर भी भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के नेताओं को पांचों सीट नहीं जीत पाने का गम सता रहा है।

इसी कारण कांग्रेस नागपुर की पराजय को प्रचारित कर भाजपा को मिली खुशी नहीं मनाने दे रही है। राजनीति के नए पैंतरे में दूसरी-तीसरी पंक्ति के नेता अधिक फंस रहे हैं। महागठबंधन में कुछ ठीक-ठाक नहीं चलने का प्रमाण दे रहे हैं। जिस विचार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री तथा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एवं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के एक मंच पर आने से हवा मिल गई।

फिलहाल वर्तमान में जीने और राजनीति करने वालों के लिए चुनाव परिणाम अध्ययन का विषय है, जो अक्सर वे नहीं करते हैं। दो साल के अंतराल से होने वाले विधान परिषद चुनाव छह वर्ष बाद रिक्त होने वाले स्थानों के लिए होते हैं। जिन्हें स्थानीय निकाय, स्नातक, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भरा जाता है। तीनों चुनाव के मतदाता अलग-अलग होते हैं, जो हर चुनाव में नए सिरे से तय किए जाते हैं।

यह भी माना जाता है कि मतदाता पंजीकरण में सफलता मिलने पर विजय की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस कार्य में भी वही सफल होता है, जिस पर सत्ताधारी



पक्ष की छत्रछाया रहती है। अनुभवी उम्मीदवार के पास अधिक जानकारी होने से वह चुनावी जीत के लिए उपयुक्त माना जाता है।

ताजा चुनाव में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की औरंगाबाद सीट से सतीश चव्हाण चौथी बार, नागपुर सीट से अभिजीत वंजारी दूसरी बार मैदान में थे। इसी प्रकार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की पुणे सीट से जयंत आसगांवकर और अमरावती से किरण सरनाईक दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे थे। पुणे की स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर अरुण लाड के स्थान पर हर्षदा देशमुख-जाधव पहली बार चुनाव लड़ रही थीं।

उनके विरुद्ध भाजपा की उम्मीदवार स्मिता जाधव भी पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही थीं। कुल पांच सीटों के चुनाव में चार पर पुराने प्रत्याशी थे, जिन्हें अपना स्थान बचाना था। नतीजों में नागपुर में कांग्रेस के वंजारी, अमरावती में निर्दलीय से शिवसेना शिंदे गुट में आए सरनाईक ने अपनी सीट बचा ली। पुणे(स्नातक निर्वाचन क्षेत्र) में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट ने अपना स्थान बचाए रखा।

औरंगाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चव्हाण की हार हुई, लेकिन पहले वह अविभाजित राकांपा से उम्मीदवार थे और इस बार विजेता विभाजित राकांपा के शरद पवार गुट के उम्मीदवार प्रताप सिंह पाटिल रहे। जिसे राजनीतिक और पार्टी स्तर पर बड़ा परिवर्तन नहीं माना जा सकता है।

दूसरी ओर पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के कौस्तुभ गावडे का जीतना एक उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि वह सीट पहले कांग्रेस के आसगांवकर के पास थी। यानी कुल पांच सीटों में केवल एक बदलाव हुआ, जो सत्ताधारियों के पक्ष में रहा। फिर भी भाजपा के नेताओं का शोर मचाना और शिवसेना शिंदे गुट का जवाब देना समझ से परे है।

महागठबंधन में यदि कोई समस्या थी तो वह आपसी तालमेल के साथ चुनाव नहीं लड़ने की थी। परिणामों के बाद यह कहा जा रहा है कि आपसी सामंजस्य से पांचों सीटें जीती जा सकती थीं, जो नहीं हुआ। अलग-अलग क्षमता तथा महत्वाकांक्षा के साथ तीन दलों के बने गठबंधन में हर एक की विस्तार के लिए कोशिश है।

शिवसेना शिंदे गुट स्वयं को असली शिवसेना मानता है।वह समझौतावादी बन स्वयं को कमजोर साबित नहीं करना चाहता है। उसे जब और जहां अवसर मिलता है, वह अपनी दावेदारी खड़ी कर देता है। बीते दिनों में स्थानीय निकायों के चुनावों में यह बात स्पष्ट हो चुकी है। उसके नेता अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए किसी भी स्तर के लिए तैयार हैं।

उनका मानना है कि शिवसेना में बगावत के बाद जिन नेताओं-कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, वे भी किसी आशा से बंधे हैं। जिस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसी के चलते कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इस बात को तीनों दलों के नेतृत्व ने भलीभांति स्वीकार किया हुआ है। किंतु उसे वे निचले स्तर पर पहुंचाने में विफल हैं।

यही कारण है कि महागठबंधन में एक नई सीट जीतने वाली भाजपा और अपने उम्मीदवार को विजयी बनाए रखने वाला शिवसेना का शिंदे गुट आपस में भिड़ रहे हैं। पुणे और छत्रपति संभाजीनगर में हुई पराजय के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। वह यह नहीं मान रहे हैं कि इस पराजय में गठबंधन का कोई नुकसान नहीं है। बस विधान परिषद में उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई।

भाजपा की नागपुर में हुई पराजय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय, मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के गृहनगर से जोड़ा जा रहा है। यद्यपि पिछली बार भी वहां से कांग्रेस जीती थी और इस बार उसने अपनी सीट बरकरार रखी। इसलिए उसे न तो हानि की दृष्टि से देखा जा सकता है और न ही नागपुर को विधान परिषद की एक सीट पर सीमित माना जा सकता है।

निश्चित ही राजनीति में दलीय विस्तार को विशेष महत्व प्राप्त है, जिसमें जनाधार बढ़ाना मूलभूत कार्य है। मगर काल्पनिक स्थितियों के लिए आपस में भिड़ना अंदरूनी कमजोरी की निशानी है। चुनाव में महागठबंधन के अलावा महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस और शिवसेना ठाकरे गुट के उम्मीदवार मैदान में थे।

लेकिन वहां परिणामों के बाद बेवजह शोर नहीं मचा। वैसा ही संयम दिखाने पर महागठबंधन की साख पर आंच नहीं आती। फिलहाल शोक से दरार पड़ी है, उसे मिटाने में समय लगेगा। अपेक्षित परिणामों पर किए गए अनपेक्षित हंगामे का नतीजा भुगतना पड़ेगा।

ध्वस्त हुआ नेतन्याहू के अपराजित होने का मिथक

तनवीर जाफ़री

इज़राइल के 2026 के संसदीय आम चुनावों के नतीजों के आने बाद देश में एक बार फिर राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बन गई है और किसी भी गुट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ग़ौरतलब है कि इस्राईल की 120 सदस्यों वाली नेसेट अर्थात संसद में सरकार बनाने और पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए 61 सीटों की आवश्यकता होती है। परन्तु प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिकुड पार्टी व अन्य सहयोगी दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन को कुल 53 सीटें मिली हैं। जबकि इसमें उनकी स्वयं की लिकुड पार्टी को 27 सीटें मिली हैं। 27 सीटें जीतकर लिकुड पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो ज़रूर उभरी है परन्तु इसके बावजूद नेतन्याहू का दक्षिणपंथी गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े यानी 61 सीटों तक नहीं पहुँच सका और बहुमत से 8 सीटें कम रह गया। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि उनका उद्देश्य एक मज़बूत दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सरकार बनाना है। इस चुनाव का एक और आकर्षण अरब नेतृत्व वाली पार्टियां का 19 सीटों पर जीत दर्ज करना भी है । अरब लोग इस्राईल की कुल जनसंख्या का क़रीब 21 प्रतिशत हैं। इस्राईल के इतिहास में यह अरब पार्टियों का अब तक का ऐतिहासिक व सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। जबकि गादी आइज़नकोट का मुख्य विपक्षी गठबंधन 48 सीटें जीत पाया है। माना जा रहा है कि किसी भी बड़े गठबंधन को बहुमत न मिलने के कारण अब इस्राईल में सरकार बनाने के गठबंधन की जोड़-तोड़ और बातचीत का लंबा दौर चल सकता है । निश्चित रूप से इन चुनाव परिणामों ने इस्राइली समाज के गहरे मतभेद उजागर किए हैं।

इस्राईल में हुआ यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण था इसका अंदाज़ा इसी बात से



लगाया जा सकता है कि इसमें यहूदी और अरब दोनों ही मतदाओं की ओर से रिकॉर्ड संख्या में मतदान में हिस्सा लिया गया। इसके अतिरिक्त अनेक मतदाताओं ने हज़ारों डॉलर ख़र्च कर विदेशों से आकर मतदान में हिस्सा लिया। नेतन्याहू की पार्टी व उनके नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल न होने के पीछे जो मुख्य कारण माने जा रहे हैं उनमें एक तो यह कि यह चुनाव एक ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुये जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। इसके अतिरिक्त नेतन्याहू पर 7 अक्तूबर से पहले इस्राईल की रक्षा करने में नाकाम रहने का भी आरोप है। विपक्षी नेताओं व समाज के एक बड़े वर्ग द्वारा इसकी जांच की मांग भी होती रही है, लेकिन नेतन्याहू इस जांच के लिए कभी तैयार नहीं हुये। इसलिये इस्राईली समाज का एक बड़ा वर्ग 7 अक्तूबर की घटना को एक सुनियोजित व सत्ता प्रायोजित साज़िश के संदेह से भी इनकार नहीं करता।

अब इस्राईल में नई सरकार बनाने को लेकर भी तरह तरह के क़यास लगाये जा रहे हैं। इतने अलग-अलग विचारों और राजनीतिक हितों को एक सरकार के रूप में साथ लाना अब इस्राईल की राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार बनाने के लिये क्या नेतन्याहू अपने धार्मिक सहयोगियों को छोड़कर विपक्षी गुट के दक्षिणपंथी नेताओं के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार होंगे? और क्या वे नेता, जो लंबे समय से नेतन्याहू के विरोधी रहे हैं, उनके साथ सरकार में शामिल होने के लिए तैयार होंगे? क्या विपक्षी गठबंधन अपने चुनावी वादों का बड़ा हिस्सा छोड़कर नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के लिए अरब पार्टियों के साथ सहयोग करने को तैयार है? और क्या अरब पार्टियां ऐसी सरकार में शामिल होने का जोखिम उठाएंगी, जो कुछ ही महीनों में गिर सकती हो ? यह सवाल इस्राईल के राजनैतिक भविष्य के लिये सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस बीच इस्राइल के वरिष्ठ वामपंथी डेमोक्रेट नेता यायर गोलान ने विपक्षी गुट से अरब पार्टियों के साथ साझेदारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमें अब नेतन्याहू द्वारा यहूदी और अरब वोटों के बीच किए जा रहे नस्लवादी विभाजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। चुनाव परिणामों और विश्लेषकों के रुख़ को देखें तो यह स्पष्ट है कि नेतन्याहू की कट्टर, ध्रुवीकरण करने वाली और अत्यधिक आक्रामक छवि ने उन्हें गंभीर राजनीतिक नुक़्सान पहुँचाया है। अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद से इस्राइल लगातार युद्ध की स्थिति में है। नेतन्याहू ने ईरान, गज़ा और लेबनान में सैन्य सफलताओं को भुनाने की कोशिश भी की। लेकिन देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा लगातार जारी युद्ध की अनिश्चितता, बंधकों की घर वापसी में विफलता और देश के आर्थिक नुक़्सान से थक चुका था। इसी ने नेतन्याहू की अजेय सुरक्षा प्रदाता वाली छवि को चोट पहुंचाई।

नेतन्याहू के मौजूदा गठबंधन में धुर-दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी वे यहूदी नेता भी शामिल थे, जिन्होंने वेस्ट बैंक में आक्रामक नीतियों को बढ़ावा दिया। इसके चलते इस्राइल के उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष और यूरोपीय मूल के यहूदी नागरिकों में यह डर बढ़ गया था कि यह कट्टरता इस्राइल के लोकतांत्रिक ढांचे को ख़त्म कर रही है, जिससे तेल अवीव की सड़कों पर उनके ख़िलाफ़ भारी विरोध प्रदर्शन हुए। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान नेतन्याहू ने यहूदी राष्ट्रवादियों को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया पर आक्रामक बयानबाज़ी की और अरब नागरिकों पर चुनाव चुराने का आरोप लगाया। नेतन्याहू के इस आक्रामक रुख़ ने डर पैदा करने के बजाय अरब मतदाताओं को एकजुट कर दिया, जिसके कारण उन्होंने रिकॉर्ड संख्या में बाहर निकलकर नेतन्याहू व उनके गठबंधन के ख़िलाफ़ वोट डाला। युद्ध के इस दौर में भी नेतन्याहू द्वारा कट्टरपंथी रूढ़ीवादी यहूदियों को सेना की अनिवार्य सेवा से छूट देना भी आम इस्राइलियों को रास नहीं आया, जो लंबे समय से मोर्चे पर लड़ रहे हैं। विपक्ष ने इसे भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था ।

इस्राईल के चुनाव परिणाम से यह संकेत भी साफ़ है कि नेतन्याहू ने भले ही अपनी लिकुड पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में बचा लिया हो, लेकिन उनकी आक्रामक और ध्रुवीकरण की राजनीति ने उनके विरोधियों और देश के अरब अल्पसंख्यकों को इस क़दर लामबंद कर दिया कि वे स्पष्ट बहुमत से 8 सीटें दूर रह गए। इसलिये कहना ग़लत नहीं होगा कि इस्राईल में बदलाव की चाहत रखने वाले और उनके कट्टर रवैये से असहमत लोगों ने उनके अपराजित होने के मिथक को ध्वस्त कर दिया है।

चीन को लगे 40 साल, मोदी ने 12 साल में कर दिखाया!

नीरज कुमार दुबे

बचपन में घोर गरीबी को बेहद करीब से देखने वाले और जीवनयापन के लिए रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी ने जब देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, तो उनके सामने भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी गरीबी। करोड़ों लोगों के पास न पक्का मकान था, न बैंक खाता, न शौचालय, न रसोई गैस और न ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को सरकारी योजनाओं के केंद्र में रखते हुए गरीबी के अभिशाप से देश को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया। अब इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं जिसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी मान रही हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की ताजा रिपोर्ट भारत की इसी परिवर्तनकारी यात्रा पर वैश्विक मुहर लगा रही है। विश्व बैंक की Poverty and Equity Brief, October 2026 के मुताबिक, भारत ने 2011 से 2023 के बीच अनुमानित 49.6 करोड़ लोगों को 4.20 डॉलर प्रतिदिन वाली निम्न-मध्यम आय वर्ग की गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। इस अवधि में इस श्रेणी में आने वाली आबादी का अनुपात 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत रह गया। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अत्यंत गरीबी में रहने वाली आबादी का अनुपात 2011 के 27.1 प्रतिशत से घटकर 2023 में महज 2.6 प्रतिशत रह गया। विश्व बैंक ने भारत की इस प्रगति को दुनिया में गरीबी घटने की सबसे तेज प्रक्रियाओं में से एक बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत घरेलू उपभोग, रोजगार में वृद्धि, विशेषकर महिलाओं की बढ़ती रोजगार भागीदारी और खाद्य सब्सिडी सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखा जाये तो प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है कि गरीबों को केवल आर्थिक सहायता देने के बजाय उन्हें बुनियादी सुविधाओं और वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जाए। जनधन योजना के जरिए करोड़ों बैंक खाते खुले। आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का रास्ता मजबूत किया। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने गरीब परिवारों के जीवन स्तर को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिली। इसके साथ ही मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए रोजगार, उद्यमिता और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का प्रयास हुआ। साथ ही कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट, महंगाई और वैश्विक व्यापारिक तनाव के बीच भारत ने अपनी आर्थिक विकास गति बनाए रखने की कोशिश की है। बुनियादी ढांचे पर सरकारी निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, घरेलू उपभोग और मजबूत बैंकिंग व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की क्षमता ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन को भी अधिक प्रभावी बनाया है। यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या दुनिया के किसी दूसरे नेता ने नरेंद्र मोदी जैसी आर्थिक उपलब्धि इतने कम समय में हासिल की है? तुलनात्मक रूप से देखें तो चीन ने 1978 के बाद लगभग चार दशकों में करीब 77 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ऐतिहासिक दावा किया था। वहीं भारत ने विश्व बैंक के अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, 2011 से 2023 के बीच महज 12 वर्षों में 49.6 करोड़ लोगों को 4.20 डॉलर प्रतिदिन वाली निम्न-मध्यम आय वर्ग की गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया। अत्यंत गरीबी का अनुपात भी इसी अवधि में 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत रह गया। चीन की चार दशक लंबी यात्रा के मुकाबले भारत की 12 वर्षों की यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण है। इस उपलब्धि का राजनीतिक और नीतिगत महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस अवधि के अधिकांश वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते हैं। 2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने गरीबों के बैंक खाते खोलने, सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने, मुफ्त राशन, आवास, रसोई गैस, स्वास्थ्य बीमा, स्वच्छता और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया।



ब्रजभूमि

भगवान श्रीकृष्ण धन्य हैं, उनकी लीलाएं धन्य हैं और इसी प्रकार वह भूमि भी धन्य है, जहां वह त्रिभुवनपति मानस रूप में अवतरित हुए और ब्रजभूमि जहां उन्होंने वे परम पुनीत अनुपम अलौकिक लीलाएं कीं।

जहां कृष्ण ने की अनेक लीलाएं..

हिंदुस्थान में अनेक तीर्थ स्थान हैं, सबका महात्म्य है, भगवान के और-और भी जन्मस्थान हैं पर यहां की बात ही कुछ निराली है। यहां के नगर-ग्राम, मठ-मंदिर, वन-उपवन, लता-कुंज आदि की अनुपम शोभा भिन्न-भिन्न ऋतुओं में भिन्न-भिन्न प्रकार से देखने को मिलती है।

अपनी जन्मभूमि से सभी को प्रेम होता है फिर वह चाहे खुला खंडहर हो और चाह सुरम्य स्थान, वह जन्मस्थान है, यह विचार ही उसके प्रति होने के लिए पर्याप्त है। इसी से सब प्रकार से सुंदर द्वारका में वास करते हुए भी भगवान श्रीकृष्ण जब ब्रज का स्मरण करते थे, तब उनकी कुछ विचित्र ही दशा हो जाती थी।

जब ब्रज भूमि के वियोग से स्वयं ब्रज के अधीश्वर भगवान श्रीकृष्ण का ही यह हाल हो जाता है, तब फिर उस पुण्यभूमि की रही-सही नैसर्गिक छटा के दर्शन के लिए, उस छटा के लिए जिसकी एक झांकी उस पुनीत युग का, उस जगद् गुरु का, उसकी लौकिक रूप में की गई अलौकिक लीलाओं का अद्भुत प्रकार से स्मरण कराती, अनुभव का आनंद देती और मलिन मन-मंदिर को सर्वथा स्वच्छ करने में सहायता प्रदान करती है, भावुक भक्त तरसा करते हैं।

इसमें आश्चर्य ही क्या है? नैसर्गिक शोभा न भी होती, प्राचीन लीलाचिह्न भी न मिलते होते तो भी केवल साक्षात् परब्रह्म का यहां विग्रह होने के नाते ही यह स्थान आज हमारे लिए तीर्थ था, यह भूमि हमारे लिए तीर्थ थी, जहां की पावन रज को ब्रह्मज्ञ उद्धव ने अपने मस्तक पर धारण किया था।

वह ब्रजवासी भी दर्शनीय थे, जिनके पूर्वजों के भाग्य की साराहना करते-करते भक्त सूरदास के शब्दों में बड़े-बड़े देवता आकर उनकी जूठन खाते थे, क्योंकि उनके बीच में भगवान अवतरित हुए थे।

ब्रज-वासी-पटतर कोउ नाहिं।
ब्रह्म सनक सिव ध्यान न पावत, इनकी जूठनि लै लै खाहिं॥
हलधर कह्यौ, छाक जेंवत संग, मीठो लगत सराहत जाहिं।
सूरदास प्रभु जो विश्वम्भर, सो ग्वालनके कौर अघाहिं॥

तब फिर यहां तो अनन्त दर्शनीय स्थान हैं, अनन्त सुंदर मठ-मंदिर, वन-उपवन, सर-सरोवर हैं, जो अपनी शोभा के लिए दर्शनीय हैं और पावनता के लिए भी दर्शनीय हैं। सबके साथ अपना-अपना इतिहास है। यद्यपि मुसलमानों के आक्रमण पर आक्रमण होने से ब्रज की सम्पदा नष्टप्राय हो गई है। कई प्रसिद्ध स्थानों का चिह्न तक मिट गया है, मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी हैं, तथापि धर्मप्राण जनों की चेष्टा से कुछ स्थानों की रक्षा तथा जीर्णोद्धार होने से वहां की जो आज शोभा है, वह भी दर्शनीय ही है।

कैलाश परिक्रमा से मिट जाते हैं जन्मों के कष्ट

तिब्बत स्थित कैलास पर्वत को शास्त्रों में कैलास को मेरू गण पर्वत, रजतगिरि आद नाम। से भी वर्णित किया गया है। इतना ही नहीं कैलास पर्वत शिव आराधना का सर्वोच्च स्थल भी माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार यह भगवान आशुतोष व पार्वती का स्थायी निवास है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव व पार्वती के नृत्य करने से इसका नाम कैलास हुआ। उपासकों का मत है कि स्वयं भू कैलास पर भगवान शंकर का विशाल राजप्रसाद है। जहां केवल ब्रह्म, विष्णु एवं महेश आदि देवों का ही प्रवेश संभव है। कैलास न केवल सनातनधर्मियों बल्कि जैन, बौद्ध व तिब्बितयों के लिए प्रारंभ से ही श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है।

यहां विराट एवं अतिभव्य लिग शदल कमल के मध्य में अवस्थित है। इस पवित्र लिग पर सदैव त्रिपुंड की रचना प्रकृति के पावन करों से होती है। तिब्बती भाषा में कैलास को पवित्र हिम से जाना जाता है। यही कारण है कि तिब्बती कैलास परिक्रमा दंडवत लेट-लेट कर पूर्ण करते हैं। कैलास परिक्रमा मार्ग दरचन से प्रारंभ होता है जो लगभग 54 किलोमीटर का है। मार्ग के क्रम में न्याडीगुम्का, दिराफुक, दोल्माघाटी, गौरीकुंड व जुन्धुलुफुक आदि मनोहारी व रमणीक स्थल पड़ते हैं। इनमें समुद्र तल से 18600 फीट की ऊंचाई पर स्थित दोल्माघाटी कैलास परिक्रमा का सर्वोच्च उच्च स्थल है। 14600 फीट की ऊंचाई पर कैलास से 20 मील पूर्व ही दो पवित्र सरोवर राक्षसताल व मानसरोवर बरबस ही उपासकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राक्षसताल के संबंध में वर्णित है कि इसी स्थल पर लंकापति रावण ने खड़े होकर भगवान आशुतोष की अर्चना की थी जबकि मानसरोवर में भगवती सती की दाहिनी हथेली गिरी थी। ऐसा मत है कि यहां की शक्ति दाक्षयाणी व भैरव अमर हैं। ग्रीष्म ऋतु में मानसरोवर के पवित्र जल में तैरते हुए राजहंस व उत्ताल तरंगों की सुमधुर ध्वनि शैल शिखरों से प्रतिध्वनित होकर उत्पन्न नैसर्गिक संगीत का खुशनुमा वातावरण उपासकों को प्रकृति व अध्यात्म के समीप खींच लाती है जिससे उपासक को अलौकिक शांति का अनुभव होता है। जैन ग्रंथों में जहां मानसरोवर को पद्मपद से वर्णित किया गया है। मानसरोवर के पश्चिम में स्थित राक्षसताल की छटा ही निराली है। मानसरोवर स्थित मां शक्ति की प्रतिमा पाषाण रूप में है। जहां मां भगवती की अर्चना होती है। विभिन्न साहित्यकारों व कवियों ने अपने साहित्य में मानसरोवर की महत्ता का सुंदरतम वर्णन किया है जिनमें कवि कालिदास के मेघदूत आदि ग्रंथ मुख्य हैं। कैलास के अप्रतिम सौंदर्य व भगवान शंकर के सर्वोच्च उपासना स्थल होने के कारण उपासक प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कैलास परिक्रमा हेतु जाते हैं। पुराण में वर्णित है कि कैलास की एक प्रक्रिमा से ही जन्म- जन्मांतर के पाप कर्म देर हो जाते हैं।



दांम्पत्य जीवन को बनाएं तनावरहित

आज का यह बदलता परिवेश सिर्फ जीवनशैली में ही प्रभाव नहीं डालता अपितु वैवाहिक जीवन में भी परेशानी का सबब बन रही है। कई दम्पतियों में आपसी सामंजस्य एवं प्रेम का अभाव देखने को मिल ही जाता है। दम्पति में नौबत तलाक तक भी पहुंच जाती है। ऐसे में न सिर्फ प्रभावित दम्पति, वरन् पूरा परिवार परेशान हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए ये उपाय लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं-

- यदि किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री के कारण दाम्पत्य क्लेशपूर्ण बन रहा है, तो 7-7 गोमती चक्र, लघु नारियल एवं लघु शंख लें। इन्हें सवा गज के नए पीले वस्त्र में बांध लें। इसे प्रभावित (पति अथवा पत्नी) पर से सात बार उसार का बहते पानी में बहा दें। बहाने के बाद पीछे मुड़कर देखे बगैर सीधे घर लौट आएं।
- यदि दम्पति अथवा समूचे परिवार में वैचारिक मतभेद रहता है, तो प्रातःकाल उठते ही जिस मटके से परिवार के सभी सदस्य जल पीते हैं, उससे एक लोटा पानी भरें और उसे पूरे घर के प्रत्येक कक्ष में तथा छत पर छिड़कें। इस दौरान किसी से बात नहीं करें, साथ ही मन ही मन ॐ शांति का निरंतर उच्चारण करते रहें।
- परिवार में यदि पति-पत्नी के मध्य क्लेश रहता हो अथवा अन्य पारिवारिक सदस्यों के मध्य वैचारिक मतभेद अधिक रहते हों, तो प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जपें-

धां धीं धूं धूर्जटेः पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी।
क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवि शां शीं शूं मे शुभं कुरु॥

- नवरात, दीपावली किसी भी शुभ मुहूर्त में घर में तुलसी का पौधा लगाएं। उसमें प्रतिदिन सायंकाल घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे परिवार अथवा प्रभावित दम्पति में सुख-शांति कायम रहेगी।

ऐसे लोगों को मिलती है कैरियर में कामयाबी

आज हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए निरंतर प्रयोग करता रहता है। अच्छा कैरियर किसे पसंद नहीं होता। अच्छे कैरियर के लिए युवा तरह-तरह कि जतन किया करते हैं। लेकिन जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी है सही कैरियर का चुनाव। क्योंकि अक्सर कैरियर का सही चुनाव नहीं कर पाने के कारण ही व्यक्ति को जीवन में बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती है। अंक ज्योतिष में कैरियर के चुनाव के लिए एक बहुत ही आसान तरीका बताया गया है। इस तरीके को आजमाएं तो आप खुद ही अपने लिए सही कैरियर का चुनाव कर पाएंगे और अपने क्षेत्र में कामयाब व्यक्ति कहलाएंगे।

अंक ज्योतिष अनुसार हर व्यक्ति का एक मूलांक होता है। इस अंक को ज्ञात करके व्यक्ति अपने लिए सही कैरियर का चुनाव करे तो कामयाबी उसके कदम चूमती हैं क्योंकि मूलांक जिस क्षेत्र में कैरियर का संकेत देता है उस क्षेत्र में सफलता के लिए जो गुण चाहिए वह व्यक्ति में मौजूद होता है। जैसे किसी व्यक्ति का मूलांक 1 होता है तो उनमें नेतृत्व की योग्यता होती है। ऐसे व्यक्ति राजनीति एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कामयाब होते हैं। वकालत के अलावा जिन क्षेत्रों में अधिक जोश और उत्साह की जरूरत होती है जैसे सेना, पुलिस के क्षेत्र में इन्हें सफलता मिल ही जाती है। फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाईनर, नाविक, नौसेना, ठेकेदारी, व्यवसाय एवं शिल्पकला के क्षेत्र में भी यह कामयाब होते हैं।

कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए अपनाएं यह उपाय

देश और दुनिया में हो रहे विकास से लोगों विलासिता का सुख भोगने से अपने आप को कभी दुर नहीं रख पाते। इन सुखों के लिए लोग कर्ज लेने से भी पीछे नहीं हटते। जबकि एक तरह से कर्ज मानव जीवन के लिए अभिशाप होता है। जिस व्यक्ति पर कर्ज है वो व्यक्ति जिन्दा रहते हुए भी चलती - फिरती लाश के समान है। लेकिन इन उपायों से आप कर्ज को जल्द से जल्द से चुकता कर सकते हैं-

1. अगर आप कर्ज की प्रथम किश्त शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करते है तो शीघ्र आप ऋ+ण से मुक्ति पा लेंगे।
2. घर का सारा कबाड़ अमावस्या या शनिवार को घर से बाहर करें।
3. मंगलवार को कभी क़र्ज़ न लें।
4. प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ स्फटिक श्री यंत्र के सामने करने से लक्ष्मी का आगमन होता है।
5. कभी भी बुधवार को क़र्ज़ न दें।
6. 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में 5-5 पीस मीठे देसी घी के रोट का भोग लगाए।
7. व्यवसाय, मकान बनवाने हेतु कर्ज जन्मकुंडली की विवेचना करवाने के पश्चात लें।
8. प्रत्येक मंगलवार ऋ+ण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ अवश्य करें।
9. सुबह उठते ही सबसे पहले एक मुट्ठी चावल पंक्षियों को चुगने के लिए डालिए।
10. घर में कभी कोई भी मेहमान या अचानक कोई भी आए कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं नहीं तो पानी तो अवश्य ही पिलाएं।
11. शराब, मांस, नशे की चीजों से पूरी तरह से दूर रहें।

जीवन में रंगों को महत्व

कई लोगो को सादा जीवन पसंद है तो कईयों को रंगीन। क्या कभी आपने सोचा है कि इन रंग-बिरंगे रंगों को हमारे जीवन में क्या महत्व है। रंगों का हमारे जीवन व स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कहा जाता हे कि रंग नेत्रों के माध्यम से हमारे मानस में प्रविष्ट होते हैं एवं हमारे स्वास्थ्य, चितन, आचार-विचार आदि पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः उचित रंगों का प्रयोग कर हम वांछित लाभ पा सकते हैं। किसी जातक की सफलता उसके कर्मों और कुछ हद तक लाइफस्टाइल पर भी निर्भर करती है। वैसे तो प्रत्येक दिन का अपना अपना महत्व होता है लेकिन ज्योतिष के अनुसार सप्ताह के दिनों का संबंध ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है।प्रत्येक दिन का एक नंबर होता है। उन रंगों का चयन करके अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। रंग हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं तथा हमारी सफलता व असफलता के कारक भी बनते हैं। शुभ रंग भाग्योदय कारक होते हैं और अशुभ रंग भाग्य में कमी करते हैं।

सोमवारः सफेद	मंगलवारः लाल
बुधवारः हरा	गुरुवारः पीला
शुक्रवारः सफेद	शनिवारः काला
रविवारः नारंगी	

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

भाजपा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के 3 विधायक



नईदिल्ली। पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि पार्टी के तीन विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोमवार को हरमीत सिंह पठानमाजरा, चेतन सिंह जौरामाजरा और कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये नेता दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचे और पार्टी में आधिकारिक तौर पर शामिल होने से पहले भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देखे गए। पठानमाजरा और जौरामाजरा ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जबकि सिंह ने सोमवार को अपना इस्तीफा सौंपा। ये इस्तीफे तब आए हैं जब आप ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए 40 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। हालांकि, पार्टी ने सनौर और समाना विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी, जिनका प्रतिनिधित्व क्रमश: पठानमाजरा और जौरामाजरा करते हैं।

आजम की ईडी गिरफ्तारी याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट



नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन के नए मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की याचिका इस सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जा सकती है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने खान के वकील निजाम पाशा की दलीलों पर संज्ञान लिया और याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई हो सकती है। रविवार को गाजियाबाद की एक विशेष अदालत ने 78 वर्षीय खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। खान के वकील ने बताया था कि जौहर ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता को गाजियाबाद की विशेष अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले, खान को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया था।

अमित शाह की पदयात्रा पर संजय राउत का तंज



नई दिल्ली । शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सोमवार को भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने वाले अब इसे बचाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा की ओर से हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित होने वाली लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा पर तंज कसा। मीडिया से बातचीत में राउत ने कहा, उन्हें ऐसा करने दीजिए। लोकतंत्र को नष्ट करने वाले ही इसे बचाने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। इस तरह की विडंबना दूसरे देशों में भी देखने को मिलती थी। राउत ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित चलो दिल्ली रैली को लोकतंत्र की रक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित बताया। उन्होंने इसकी तुलना वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण के समर्थन में हुई रैली से की। उन्होंने कहा कि यह रैली लोकतंत्र, संविधान, स्वतंत्रता और नागरिक आजादी को बचाने के मुद्दों पर आयोजित की गई थी।

भाजपा का प्रोपेगेंडा पंक्चर जमकर हुई खरीदारी : जयराम



नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोमवार को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि रैली को बदनाम करने और लोगों को दिल्ली आने से रोकने के लिए व्यापारियों को नुकसान होने और बाजार बंद रहने का डर फैलाया गया था। हालांकि, उनके मुताबिक भाजपा का यह दुष्प्रचार पूरी तरह नाकाम रहा और दिल्ली के कारोबारियों को इसका फायदा मिला। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा का पूरा प्रोपेगेंडा पंक्चर हो गया है। उन्होंने कहा कि जब देशभर से लोग दिल्ली आएंगे तो वे खरीदारी भी करेंगे। ऐसे में दिल्ली में कारोबार करने वाले हर व्यापारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इस झूठे और तर्कहीन दुष्प्रचार का मकसद वोट चोरी और चुनाव आयोग की जवाबदेही जैसे असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना था।

कोलकाता निकाय चुनाव से पहले टीएमसी की हालत पतली



कोलकाता। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के दिसंबर में होने वाले चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई दिग्गज पूर्व पार्षदों ने चुनाव लड़ने से दूरी बना ली है। इनमें कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम और शोभन चटर्जी भी शामिल हैं। इसके अलावा मेयर-इन-काउंसिल के कई पूर्व सदस्य और बोरो चेयरमैन भी चुनावी मैदान में उतरने के इच्छुक नहीं हैं। दिग्गज नेताओं के पीछे हटने से तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़ों के सामने सभी 209 वार्डों के लिए उम्मीदवार तलाशने की चुनौती खड़ी हो गई है। एक धड़े का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, जबकि दूसरे धड़े की कमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋ्नब्रत बनर्जी कर रहे हैं। बता दें कि परिसीमन के बाद नगर निगम में वार्डों की संख्या 144 से बढ़कर 209 हो गई है। चार बार तृणमूल कांग्रेस के विधायक रहे फिरहाद हकीम ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह आगामी निकाय चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वह ऋ्नब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं।

नितिन नवीन का कांग्रेस और आरजेडी पर हमला

एसआईआर प्रक्रिया पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप



नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर बिहार के लोकतांत्रिक जनादेश का अपमान करने और जनता द्वारा नकारे जाने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। 2 नवंबर को भागलपुर में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ मार्च को संबोधित करते हुए, नवीन ने कहा कि अब विपक्षी नेताओं को निर्णायक रूप से हराने का समय आ गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की निर्धारित प्रक्रिया के दौरान कोई आपत्ति नहीं जता पाए और अब वे गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की लोकतंत्र की इस पवित्र भूमि से यह संदेश मिलता है कि अब इन विपक्षी नेताओं को निर्णायक रूप से हराने का समय आ गया है। अगर कांग्रेस पार्टी अभी भी सबक नहीं सीखती है, तो जनता उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी और उनकी ऐसी करारी हार सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा।

नबिन ने आगे कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जनादेश का अपमान करना, खुद बिहार की जनता का अपमान करने के बराबर है। स्ड्रक्र प्रक्रिया की आलोचना पर उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था, जिसका कांग्रेस और आरजेडी ने कोई उपयोग नहीं किया।

उन्होंने कहा कि आज जब भाजपा और एनडीए गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरे देश में पदयात्रा निकाल रहे हैं, तब विपक्ष - जो कल दिल्ली के रामलीला मैदान में दिखा था - झूठ के बीज बोने में व्यस्त था। एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत यहीं बिहार से हुई थी, और कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऐसे ही कई झूठ फैलाने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है- मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पूरे 60 दिनों का समय दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के पास इतने कम कार्यकर्ता थे कि कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया। अपनी चिंताओं को उठाने के लिए हर स्तर पर मिले मौकों का इस्तेमाल करने के बजाय, उन्होंने केवल दिखावटी आंसू बहाना चुना। और जब पूरी एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई, तो उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था।

सोनिया गांधी की लालू-तेजस्वी से मुलाकात

इंडिया ब्लॉक में दिया एकजुटता का संदेश



नई दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में हुई रैली के बाद इस मुलाकात को विपक्षी एकजुटता के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

ऐसे समय में जब विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग को घेर रहा है। कांग्रेस और राजद के शीर्ष नेताओं की यह बैठक गठबंधन की आगे की रणनीति के संकेत देती है।

रामलीला मैदान की रैली में तेजस्वी यादव ने वोट चोरी के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी की शुरुआत बिहार से हुई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को %दो नंबरी सरकार% बताते हुए उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में इस बार वोट चोरों के खिलाफ महाभारत का आयोजन किया गया है। महाभारत के शकुनि और उसके पासों का उदाहरण देते हुए तेजस्वी ने चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने इस लड़ाई को देश के मतदाताओं और धोखेबाजों के बीच की लड़ाई बताया।

तेजस्वी ने अपने संबोधन में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने विपक्षी दलों से एकजुट होकर भाजपा को हराने का आह्वान किया। इससे साफ है कि राजद इस मुद्दे को केवल बिहार तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की साझा राजनीतिक मुहिम बनाना चाहता है।

बिहार की राजनीति में कांग्रेस और राजद का साथ बने रहना इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। राजद के पास राज्य में अपना मजबूत संगठन और सामाजिक आधार है, जबकि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेटवर्क और अन्य विपक्षी दलों के साथ समन्वय की भूमिका है। काफी समय से दोनों दलों के बीच तालमेल बना हुआ है तो विपक्ष को साझा मुद्दों पर आवाज उठाने, कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने और भाजपा के खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाने में मदद मिलती रही है।

दोनों दलों के बीच किसी तरह की दूरी या सीटों को लेकर खींचतान विपक्षी एकता के दावे को कमजोर कर सकती है। बीते बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अच्छा तालमेल रहा था। ऐसे में सोनिया गांधी की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात को बिहार में गठबंधन के रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की रणनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तालमेल भी अहम रहने वाला है। दोनों दलों के सामने सीटों के बंटवारे और अपने-अपने संगठनात्मक हितों को साधने की चुनौती है। रिपोर्टों के मुताबिक, गठबंधन को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत के बावजूद सीटों के सवाल पर दबाव और मतभेद की स्थिति बनी हुई है।

ऐसे में राजद और कांग्रेस के बीच बेहतर समन्वय का असर विपक्षी गठबंधन की व्यापक रणनीति पर भी पड़ सकता है। इससे कांग्रेस को क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ संवाद बनाए रखने में मदद मिलेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की बातचीत में राजद के साथ संबंध दोनों पार्टियों के लिए पुल का काम कर सकते हैं।

तेजस्वी यादव का यूपी में भाजपा को हराने का आह्वान भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। विपक्ष की कोशिश है कि एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को चुनावी बहस में बनाए रखा जाए और इसे अलग-अलग राज्यों में साझा अभियान का रूप दिया जाए।

सुधांशु त्रिवेदी का इंडिया गठबंधन पर हमला

राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती



भुवनेश्वर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सबसे बेहतर स्थिति में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा और एनडीए सरकार के साथ, भारत इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सबसे बेहतर स्थिति में आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं। परसों ही, विश्व बैंक ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत सरकार ने पिछले 12-13 वर्षों में लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जबरदस्त सफलता हासिल की है।

उन्होंने आगे कहा, विश्व बैंक के अनुसार, 2011-12 में जहां 27 प्रतिशत लोग अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे थे। वहीं अब यह आंकड़ा घटकर केवल 2.6 प्रतिशत रह गया है। 2011-12 में जहां 57 प्रतिशत लोग प्रतिदिन 4.2 डॉलर (आज के हिसाब से लगभग 400-425 रुपये) से कम कमाते थे वहीं आज इस स्तर से नीचे केवल 16 प्रतिशत लोग हैं।

सुधांशु त्रिवेदी आगे कहते हैं, %एआई, रक्षा उत्पादन और उभरती हुई तकनीकों जैसे क्षेत्रों में भारत जिस तेजी से वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि कुछ ताकतों को यह विकास रास नहीं आ रहा है। ये ताकतें भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं, और दुर्भाग्य से, ऐसा लगता है कि विपक्ष इनके हाथों की कठपुतली बन गया है। भारत गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन, विपक्ष का मौजूदा रवैया बताता है कि वे इस प्रगति या राष्ट्रीय स्वाभिमान की बढ़ती भावना से खुश नहीं हैं।

इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधे हुए कहा, फिलहाल, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। राहुल गांधी ने एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है, जिसमें वे दावा करते हैं कि सत्ता-विरोधी लहर चल रही है और उनकी पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा राहुल, आप केवल अराजकता फैला रहे हैं, लेकिन ठोस और वास्तविक तथ्य क्या कहते हैं? पिछले पच्चीस वर्षों से ओडिशा में कांग्रेस का एक भी मुख्यमंत्री नहीं रहा है।

खेल
प्रमुख समाचार

पीवी सिंधु ने हाइलो ओपन जीतकर खिताब अपने नाम किया



जर्मनी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने एक बार फिर अपने शानदार खेल से देश का नाम रोशन किया है। सिंधु ने जर्मनी में खेले गए हाइलो ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में डेनमार्क की लाइन केजर्सफेल्ट को सीधे गेमों में 21-12, 21-14 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सिंधु ने मौजूदा सीजन का अपना दूसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया है।

पीवी सिंधु ने फाइनल मुकाबले में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने पहला गेम महज 17 मिनट में 21-12 से जीतकर डेनमार्क की खिलाड़ी पर दबाव बना दिया। इसके बाद दूसरे गेम में भी सिंधु ने अपनी लय बरकरार रखी और 21-14 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारतीय शटलर ने यह फाइनल केवल 39 मिनट में जीतकर शानदार अंदाज में खिताब पर कब्जा किया।

सिंधु का हाइलो ओपन में प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। उन्होंने फाइनल तक के सफर में एक भी गेम नहीं गंवाया। अपने अभियान की शुरुआत उन्होंने भारतीय खिलाड़ी प्रकृति भरत को हराकर की। इसके बाद फ्रांस की रोजी ओक्टाविया पंकासारी और जर्मनी की अमाली शुल्ज को मात देकर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उन्होंने भारत की ही अनमोल खरब को 21-13, 21-16 से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया।

पीवी सिंधु के लिए यह साल खिताब के लिहाज से शानदार रहा है। उन्होंने जुलाई में जापान ओपन 2026 के फाइनल में जापान की तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को हराकर खिताब जीता था। अब हाइलो ओपन जीतकर उन्होंने इस सीजन का दूसरा बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम कर लिया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

तेल की कीमतों में गिरावट के चलते सेंसेक्स 1233 अंक उछला

नई दिल्ली। सोमवार को शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक काफी तेजी के साथ बंद हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों के बाद उसमें आई भारी तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के चलते सेंसेक्स 1,233 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी 23,440.80 के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी फंडों के आने और घरेलू मैक्रो इंडिकेटर्स (आर्थिक संकेतकों) के सकारात्मक रहने से भी बाजार का उत्साह बढ़ा। लगातार तीसरे दिन तेजी दिखाते हुए, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,233.25 अंक (यानी 1.66 प्रतिशत) उछलकर दिन के उच्चतम स्तर 75,692.78 पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 387.70 अंक (यानी 1.68 प्रतिशत) की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तर 23,440.80 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 11.64 प्रतिशत की जोरदार तेजी आई।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शानदार रहा अक्टूबर

नई दिल्ली। अक्टूबर में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जोरदार गतिविधियां देखने को मिलीं। त्योहारी मांग के चलते देश में कारों की बिक्री पहली बार एक महीने में 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गई। वहीं, डिजिटल भुगतान के मोर्चे पर भी नया रिकॉर्ड बना और यूपीआई लेनदेन 25 अरब के आंकड़े को पार कर गया। इसके अलावा जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 23 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, देश का कच्चे तेल और एलएनजी का आयात भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये आंकड़े घरेलू मांग में मजबूती के साथ ऊर्जा जरूरतों में बढ़ोतरी को भी दर्शाते हैं। अक्टूबर में देश में यात्री वाहनों की बिक्री करीब 14 फीसदी बढ़कर 5.30 लाख यूनिट रहने का अनुमान है। पहली बार किसी एक महीने में कारों की बिक्री 5 लाख यूनिट के पार पहुंची है।

भारत-यूरोपीय संघ ने की एफटीए लागू करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लागू करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। इस समझौते पर दिसंबर में हस्ताक्षर होने हैं। आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पिछले सप्ताह ब्रसेल्स यात्रा के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की। अग्रवाल ने यूरोपीय आयोग के व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा महानिदेशालय की डिट्टे जुल जॉर्गनस, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी महानिदेशालय के कोएन डोएन्स और कराधान एवं सीमा शुल्क संघ महानिदेशालय के गेरासिमोस थॉमस से मुलाकात की। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इन बैठकों में सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुगमता और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों पक्षों ने 27 जनवरी को इस समझौते के लिए बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी।

खुदरा कारोबार में ई-इनवॉइसिंग का पायलट शुरू करने की तैयारी

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे को व्यापक बनाने और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार 1 अप्रैल, 2027 से खुदरा कारोबार में ई-इनवॉइसिंग की पायलट परियोजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत चुनिंदा व्यावसायिक क्षेत्रों में दुकानदारों और कारोबारियों को आम ग्राहकों को जारी किए जाने वाले बिलों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना होगा। घटनाक्रम से जुड़े सरकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खुदरा कारोबार में होने वाले लेनदेन की निगरानी बढ़ाना और वास्तविक बिक्री का जीएसटी रिटर्न में घोषित आंकड़ों से मिलान करना है। फिलहाल कारोबारी रिटर्न में कुल बिक्री का ब्योरा देते हैं और प्रत्येक खुदरा लेनदेन की अलग-अलग जानकारी देना अनिवार्य नहीं है।

देश में कम इस्तेमाल होने वाली दलहन फसलों की अनदेखी जारी

सुरिंदर सूद

भारत में दलहन फसलों की उपलब्ध स्थानीय किस्मों का उचित इस्तेमाल नहीं होना समझ से परे हैं। यह बात इसलिए भी अधिक हैरान करने वाली है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां दलहन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है और एक बड़ी आबादी कुपोषण की शिकार है। इतना ही नहीं, दलहन की जरूरत पूरी करने के लिए देश को इसका बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है।

दलहन फसलों की कुल 14 उपलब्ध किस्मों में केवल 8 ही नियमित रूप से उगाई और खाई जाती हैं। बाकी किस्में पूरी तरह नजरअंदाज हो गई हैं या कुछ खास इलाकों में बहुत छोटे स्तर पर उगाई और इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। इनमें कई ऐसी किस्में हैं जिनमें पोषक तत्व काफी मात्रा में मौजूद हैं। अगर इनकी खेती पर ध्यान दिया जाए तो इससे उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे एवं सीमांत किसानों को भी बहुत फायदा हो सकता है।

किसान पारंपरिक रूप से पानी की कमी वाले इलाकों में कम उपजाऊ या सूखी जमीन पर इन्हें उगाते रहे हैं मगर बाजार में इनकी मांग कम है। इसे देखते हुए इन किस्मों की खेती बंद हो गई है।

इन कम इस्तेमाल होने वाली किस्मों में मोठ, खेसारी, कुलथी, बाकला या काला मटर, सुतरी या लाल बीन और लाल मूंग या लाल चौरी शामिल हैं। इनकी खेती कुछ सीमित इलाकों तक ही सिमट कर रह गई है और इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर ही होता है। ये दलहन फसलें कई तरह के इस्तेमाल में लाई और आसानी से उगाई जा सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये काफी फायदेमंद हैं। इन खूबियों को देखते हुए इन्हें और बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाने की की जरूरत है।

मगर अफसोस की बात है कि दलहन की



इन किस्मों को कृषि वैज्ञानिकों ने भी नजरअंदाज कर दिया है इसलिए इन्हें अक्सर 'अनाथ फसलें' कहा जाता है। इनकी उत्पादकता, दाने की गुणवत्ता, प्रसंस्करण और बाजार में बिकने की क्षमता बेहतर बनाने के लिए या इनकी अधिक पैदावार देने वाली किस्में विकसित करने के लिए पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास कार्य नहीं हुए हैं।

पोषण सुरक्षा मजबूत करने के लिए प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ानी बहुत जरूरी है। ऐसे में इन कीमती दलहन फसलों के प्रति ऐसी उदासीनता बिल्कुल भी उचित नहीं है।

देश में दलहन फसलों की पैदावार में केवल पांच तरह की दालों का दबदबा है। इन किस्मों की कुल उत्पादन और खपत में 90 फीसदी हिस्सेदारी है। इनमें अरहर, चना, मूंग, उड़द, और मसूर शामिल हैं। बाकी 10 प्रतिशत हिस्सा राजमा, लोबिया और मटर के नाम है।

कम इस्तेमाल होने वाली दालों में मौजूद खूबियों का इस्तेमाल करने के कई अच्छे एवं मजबूत कारण हैं। पहली बात तो यह है कि इनसे दलहन फसलों की घरेलू आपूर्ति बढ़ सकती है जिससे दलहन का आयात कम होगा। वर्ष 2024-25 में दलहन आयात 70 लाख टन और वर्ष 2025-26 में 60 लाख टन रहा था।

इसके अलावा, ये दालें ऐसी खराब गुणवत्ता वाली जमीनों पर भी उग सकती हैं जो मुख्य अनाज और व्यावसायिक फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होतीं। ये फलियों वाली फसल होने के कारण हवा से नाइट्रोजन मिट्टी में स्थिर कर ऐसी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकती हैं।

लिहाजा, ये फसलें बंजर जमीन फिर उर्वर बनाने का एक प्रभावी जरिया बन सकती हैं। भारत में ऐसी जमीन काफी बड़ी मात्रा में हैं जो लगभग 9.8 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं। साथ ही, इन फसलों में नकद निवेश की बहुत कम जरूरत होती है इसलिए ये उन किसानों के लिए आजीविका का एक बड़ा सहारा बन सकती हैं जिनके पास ऐसी जमीन है और जो संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कृषि वैज्ञानिक इन्हें ऐसे जीन का भंडार मानते हैं जो भविष्य की फसलों में जलवायु परिवर्तन सहने की क्षमता, बीमारियों और कीटों से लड़ने की ताकत और अन्य उपयोगी गुण विकसित करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

राज्य अलंकरण एवं राज्योत्सव

समापन समारोह 2026



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

मुख्य अतिथि
श्री अमित शाह
माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार

अध्यक्षता
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विशिष्ट अतिथि
श्री अरुण साव
माननीय उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री विजय शर्मा
माननीय उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

एवं

समस्त माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, निगम, मंडल, आयोग, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण, माननीय महापौर की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित है।

03 नवंबर 2026

सायं 6.00 बजे

राज्योत्सव मैदान, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

सुशासन समृद्धि समावेशी विकास

संवर रहा छत्तीसगढ़



पीएम आवास योजना
24.54 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को पक्की छत

रेलवे का विस्तार
₹54,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन

डेस्टिनेशन छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में पर्यटन को उद्योग का दर्जा ट्राइबल हेरिटेज व ईको टूरिज्म को बढ़ावा

जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन
बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक, बस्तर पण्डुम का निरंतर आयोजन

महतारी वंदन योजना
68 लाख महिलाओं को ₹20,708 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित

कृषक कल्याणकारी योजनाओं से
₹1.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों को अंतरित

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा
बस्तर-सरगुजा के 815 गाँवों तक सुलभ परिवहन सुविधा

शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा
75 सुरक्षा कैंप बन रहे सेवा के केंद्र

सीएम हेल्पलाइन 1076
हर शिकायत की सुनवाई
हर समस्या का समाधान

सेवा सेतु
जनता के द्वार, डिजिटल सरकार
38 विभागों की 953 सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

RO No.49677/157

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.